

भोपाल में 11 वर्षीय बच्चे को मिली नई जिंदगी

छत से गिरने पर दिमाग में जम गया था खून, डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर बचाई जान

● राहुल ने विपक्षी नेताओं को बाटे प्लास्टिक बैड्स, हाथ बांधकर प्रदर्शन ● केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिले, धरना खत्म करने को कहा, राहुल, अखिलेश हिस्सासत में

भोपाल (नप्र)। भोपाल में छत पर खेलते समय गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए 11 वर्षीय रोहित की जटिल ब्रेन सर्जरी कर डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। हृदय में रोहित के सिर में गंभीर चोट लगी थी और उसके मस्तिष्क में खून जमा हो गया था। करोंद स्थित अटल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञों ने तत्काल ऑपरेशन कर स्थिति को नियंत्रित किया। अब बच्चे की हालत स्थिर है और वह सामान्य रूप से बातचीत कर रहा है। जानकारी के अनुसार, रोहित घर की छत पर खेल रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। हृदय से बाढ़ वह बेहोश हो गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने



प्राथमिक जांच के बाद सीटी स्कैन कराया। जांच में सामने आया कि रोहित के मस्तिष्क में एक्यूट राइट टेम्पोरो-पैरिएटल एपिड्यूरल हेमेटोमा, 7 मिमी लेफ्टवर्ड मिडलाइन शिफ्ट और मल्टीपल हेमरेजिक कंट्र्यूजन जैसी गंभीर चोटें हैं।

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेपर लीक मामले में धर्मरं प्रधान और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए हैं। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गो शामिल हैं। कांग्रेसी पीएम और गृहमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शन के बीच यहां पुलिस ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी और कई कार्यकर्ताओं को हिंसासत में लिया है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन बेहद सीक्रेट रहा। राहुल समेत सभी नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गो के घर से पीएम आवास तक पैदल मार्च करके पहुंचे। जब ये लोग 100 मीटर दूर थे तब मीडिया को जानकारी दी गई। वहीं धरनास्थल से राहुल गांधी और अखिलेश को हिंसासत में ले लिया गया था।

हाथ बांधे प्रदर्शन करते हुए नजर खरगे – मल्लिकार्जुन खरगे अपने जन्मदिन के मौके पर हाथ बांधे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्योंकि यह जश्न मनाने का नहीं, बल्कि जवाबदेही मांगने का दिन है। मल्लिकार्जुन खरगे ने छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के बच्चों को दमन नहीं, न्याय चाहिए। खरगे ने एक्स ‘ पर एक पोस्ट में कहा कि वह अपने जन्मदिन पर



जश्न नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा, ‘आज जश्न मनाने का दिन नहीं है। यह जवाबदेही मांगने का दिन है। लोकतंत्र बहाल करो।’ राज्यसभा

हमारे बच्चे दमन के नहीं, न्याय के हकदार – खरगे ने छात्र-केंद्रित परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त, स्वतंत्र और योग्यता आधारित शिक्षा व्यवस्था बनाने तथा शिक्षा पर अधिक खर्च किए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में धांधली होने पर छात्रों को अनिवार्य पुनर्परीक्षा और मुआवजे का वैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। खरगे ने इस बात पर जोर दिया, ‘हमारे बच्चे दमन के नहीं, न्याय के हकदार हैं।’ खरगे का जन्म 21 जुलाई, 1942 को हुआ था।

संक्षिप्त समाचार

सोनमवांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी गीतांजलि की याचिका पर दिया फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोनम वांगचुक को सफ्दरजंग अस्पताल से मेदांता शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मेदांता उनके इलाज के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाएगा। कोर्ट ने यह आदेश उनकी पत्नी



गीतांजलि अंगमो की याचिका पर दिया है। सोनम 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई को पुलिस उन्हें जंतर-मंतर से उठाकर सफ्दरजंग अस्पताल ले गई थी। सोनम की पत्नी ने कोर्ट में याचिका लगाकर उन्हें पसंद के अस्पताल में शिफ्ट कराने की मांग की थी। उधर, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर मंगलवार को 32वें दिन प्रदर्शन जारी है। दोपहर 12 बजे तक आंदोलनकारी पहुंच गए थे।

नेपाल में 1 रुपए के सिक्के से हटाया विवादित नक्शा

बालेन शाह ने लिया फैसला, बचा बवाल, देश में घिरे

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल की बालेन शाह सरकार के नेपाल के नए डिजाइन वाले 1 रुपये के सिक्के से विवादित नक्शे को हटाने पर बवाल मच गया है। नेपाल की पूर्ववर्ती केपी ओली सरकार ने चीन के इशारे पर यह विवादित नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के लिपियाधुरा, कालापानी और



लिपुलेख को नेपाली इलाका दिखाया गया था। इस नक्शे को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अब बालेन शाह सरकार ने नेपाल के 1 रुपये के सिक्के पर से विवादित नक्शे की जगह पर एक बौद्ध मठ की तस्वीर को छापा है। इसे जहां भारत की बड़ी जीत की तरह से देखा जा रहा है, वहीं इसको लेकर नेपाल में विवाद शुरू हो गया है। नेता भीम रावल ने बालेन सरकार को धोखेबाज बताया।

अन्ना हजारे प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज से नाराज

सरकार से कहा-सभी मुद्दे सहमति से सुलझाए जा सकते हैं

मुंबई (एजेंसी)। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर-मंतर से संसद तक निकाले गए



मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस घटना के बाद देशभर की कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार की आलोचना की।

राज्यपाल-कुलसचिव को हाईकोर्ट का नोटिस

अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई, सेवानिवृत्त कर्मचारी से जुड़ा मामला ; अगली सुनवाई 4 अगस्त को

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश में संभवतः पहली बार किसी अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (आरडीवी) के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. आर.बी. दुबे की याचिका पर की गई।



हाईकोर्ट ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल, कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल और उपकुल सचिव पवन साहू को नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

डॉ. आर.बी. दुबे की नियुक्ति 10 मई 2000 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर हुई थी। उन्होंने 29 जुलाई 2006 से प्रभावी होने वाला इस्तीफा विश्वविद्यालय को सौंपा था। हालांकि बाद में उन्होंने 14 जुलाई 2006 को लिखित आवेदन देकर अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 13 जुलाई 2006 को जारी आदेश के आधार पर उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। डॉ. दुबे का तर्क था कि प्रभावी तिथि से पहले ही इस्तीफा वापस ले लिया गया था, इसलिए उसे स्वीकार करना कानूनन गलत था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को दी सरेंडर की सलाह

पूछा-गिरफ्तारी का कारण नहीं बताने का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया



इंदौर/नई दिल्ली (एजेंसी)। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने की सलाह दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि या तो

वह मेघालय सरकार की अपील पर मामले के गुण-दोष को देखते हुए फैसला करेगी या फिर सोनम को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का निर्देश देकर जांच एजेंसियों को आगे पूछताछ का अवसर देगी। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

यूपी की 50 हजार छात्राओं को मुफ्त में मिलेगी स्कूटी

- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत योगी सरकार का बड़ा तोहफा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की छात्राओं को योगी कैबिनेट से बड़ा तोहफा मिला है। मेधावी छात्राओं को परीक्षा में अच्छा करने के लिए फ्री स्कूटी देने वाली स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को आज मंगलवार 21 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दिखा दी गई है। इस योजना के तहत 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में ग्रेजुएशन में हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की टॉप-5 छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी, प्राइवेट, सेल्फ फंडिंग या अन्य मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है।

छह एमपी के शिवसेना में विलय की मंजूरी का विरोध

- सुप्रीम कोर्ट पहुंची उद्धव सेना, बेंच ने कहा-वादा नहीं कर सकते

नई दिल्ली (एजेंसी)। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 6 सांसदों की एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले को चुनौती देने के लिए पार्टी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से



गुहार लगाई कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी जाए। हालांकि, सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना (यूबीटी) की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने इस मामले को सीजेआई के सामने रखा।

- संसद में मेरा कामकाज पूरी तरह से ठप- सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने जब उद्धव सेना के वकील से तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के बारे में पूछा तो उन्होंने अदालत से कहा, एक राजनीतिक दल के तौर पर संसद में मेरा कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। ये सांसद मेरे साथ नहीं हैं। स्पीकर ने इनका दूसरी पार्टी में विलय को मंजूरी दे दी है।

‘मेड इन इंडिया’ का बजा डंका! 2026 में बढ़ा रक्षा निर्यात

रियाद/येरेवान/नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुकी भारत की अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल में आर्मेनिया और सऊदी अरब समेत 6 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। यह मिसाइल पहले से ही एसयू-30 एमकेआई फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेटेड है और इसके निर्यात को लेकर बातचीत की जा रही है। इस मिसाइल को बेचने की बात उस वक्त हो रही है जब वित्त वर्ष 2026 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपया हो गया है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र बियॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलों के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी थी। इस समझौते ने इस स्वदेशी हथियार प्रणाली में वैश्विक दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम छह देश इस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत से बात कर रहे हैं जिनमें आर्मेनिया और सऊदी अरब शामिल हैं।

6 देश भारत से खरीद सकते हैं अस्त्र मिसाइल

- सऊदी अरब, इंडोनेशिया और आर्मेनिया से बातचीत है जारी

- ‘अस्त्र’ मिसाइल रचेगी नया इतिहास- भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र मिसाइल की संख्या और कीमत को लेकर आगे बात की जाएगी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आर्मेनिया अस्त्र मिसाइलें हासिल करने के लिए भारत के साथ बातचीत के एक एडवांस स्टेज में है। इन मिसाइलों को भारतीय वायुसेना के एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमानों से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ



सफल इस्तेमाल किया गया था। आर्मेनिया और सऊदी अरब के साथ बातचीत इस हथियार प्रणाली को उनके विमानों में इंटीग्रेट करने पर

- आर्मेनिया बन चुका है भारत का बड़ा रक्षा खरीददार- आर्मेनिया पहले ही भारतीय हथियार खरीदने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। वो पहले ही आकाश सर्फेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन-लोकैटिंग रडार, 155एमएम एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम होवित्जर और एटी-ड्रोन सिस्टम खरीद चुका है। रॉयल सऊदी एयर फोर्स अमेरिकी यूरोफाइटर टाइफून जैसे अलग-अलग तरह के विमानों का इस्तेमाल करती है।

डीआरडीओ ने बनाया है अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल

अस्त्र मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बनाया है। अस्त्र एमआई-1 की स्पीड मैक 4.5 है और इसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर के बीच है। भारत ने एमआई-2 का भी टेस्ट कर लिया है जिसकी रेंज 200-240 किलोमीटर है। रैमजेट इंजन वाला एमआई-3 वर्शन अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसकी प्रस्तावित रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है।

सड़क पर धमाल, बाद में मांगी माफी

इंदौर। तात्कालिक विवाद के चलते पांच युवकों ने सड़क पर जमकर धमाला मचाया। धमाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और पांचों को थाने लाकर सबक सीखाया। इसके बाद पांचों आरोपी माफी मांगकर यह कहते नजर आए कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल, विजयनगर क्षेत्र में पांच युवक शुभम केशरवानी, हिमांशु पिता पूनमचंद साहू, उसका भाई मोहित, परमजौत पिता धामी सिंह और जगदीप पिता कृतज्ञ सिंह रविवार को क्षेत्र में घूम रहे थे। इसी दौरान किसी बात पर पांचों का आपस में विवाद हो गया। विवाद के चलते एक युवक से मारपीट की गई। घटना के बाद सभी अपने-अपने घर चले गए। सोमवार सुबह मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो फुटेज के आधार पर पांचों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। यहां सभी ने अपने कृत्य पर माफी मांगी। बाद में पुलिस ने चेतावनी दी कि दोबारा मारपीट की तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।

तस्करी में फरार युवक गिरफ्तार

इंदौर। पुलिस नशे से दूरी है जरूरी अभियान चला रही है। इसके बावजूद नशीले पदार्थ की खरीद फरोख्त थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से तस्करी मामले में फरार चल रहे युवक फिरोज उर्फ महाराज पिता अब्दुल अजीज निवासी इकबाल कालोनी को पकड़ा। फिरोज मादक पदार्थ का सप्लाय है। पूर्व में इसका साथी शाहरुख पिता अब्दुल रउफ से 13.94 ग्राम एमडी ड्रस जब्त की थी। शाहरुख ने ही फिरोज का नाम कबूला था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

इत्र की आड़ में चरस का धंधा, दो को पकड़ा

इंदौर। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 494 ग्राम चरस जब्त की। बरामद चरस की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई। आरोपी परफ्यूम और इत्र के कारोबार की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कानपुर से चरस लेकर आया एक युवक राजवाड़ा स्थित जायसवाल लॉज में खरीदार से सौदा करने वाला है। सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर कानपुर निवासी राम लखन नाईक और इंदौर निवासी मयूर सिंह चौहान को रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी में दोनों के कब्जे से 494 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि चरस की सप्लाई किस गिरोह से हो रही थी और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन शामिल हैं। कार्रवाई में निरीक्षक ममता कामले,निरीक्षक रमेश चौहान सहित एसटीएफ टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बाइक सवारों को टक्कर मारी, दो की मौत

पीथमपुर। प्रताप स्टील चौराहे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वाहन ने दोनों युवकों का सिर कुचल दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान संतोष (42) पिता त्रिवेणी झा निवासी बेरुख बेनीपुर, बिहार और राधेश्याम निवासी बोरगांव बुनुर्ग, पंधाना, जिला खंडवा के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अनियंत्रित हुई मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों के चेहरे और सिर में गंभीर चोटें आईं। घटनास्थल पर खून फैल गया, जिससे चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई। वाहनों की आवाजाही थम गई। हदसे तेज बाइक दुर्घिका जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है। पुलिसकर्मियों ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को रास्ते से हटकर यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया।

मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मारपीट की

इंदौर। खुडैल थाना क्षेत्र में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों पर ग्रामीण युवकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद छात्रों ने युवकों की बेहमी से पिटाई की। आरोप है कि इसके बाद कुछ युवकों को कार की डिक्की में डालकर अपने साथ भी ले गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मेडिकल कॉलेज और खुडैल थाने पहुंचे तथा कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। बाद में युवकों को छोड़या गया। पहले दबाव में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि मंगलवार को मामले में दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।



मुंडला नायता में बुलडोजर, सरकारी जमीन और नाला अतिक्रमण से मुक्त

ढाई एकड़ जमीन और नाले पर लंबे समय से किया अवैध कब्जा हटा



इंदौर। प्रशासन ने सोमवार को ग्राम मुंडला नायता में शासकीय भूमि पर वर्षों से जमे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब ढाई एकड़ सरकारी जमीन और नाले को कब्जे से मुक्त कराया। राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने

अभियान चलाकर टीन शेड, बाउंड्री वॉल सहित अन्य अवैध निर्माणों को हटवाया। कार्रवाई के दौरान सरकारी नाले पर किए गए कब्जे को भी पूरी तरह हटाकर उसका मूल स्वरूप बहाल किया गया। यह अभियान ग्राम मुंडला नायता की शासकीय भूमि

सर्वे क्रमांक-28 (रकबा 0.560 हेक्टेयर) पर चलाया गया। कार्रवाई का नेतृत्व एसडीएम घनश्याम धनगर ने किया। नायब तहसीलदार अशोक परमार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, नगर निगम का अमला और पुलिस बल पूरे अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रहा। भारी

मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन के मुताबिक संबंधित भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया था। प्रारंभिक आकलन में करीब ढाई एकड़ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी नाले पर हुए अतिक्रमण के कारण जल निकासी भी प्रभावित हो रही थी, जिसे हटाकर रास्ता पूरी तरह साफ कराया गया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिले में सरकारी जमीन और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किए गए अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।



लोकायुक्त की कार्रवाई

महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश, डीआईजी मनोज सिंह के मार्गदर्शन और एसपी राजेश सहाय के नेतृत्व में की गई। इंदौर, धार और मुरैना में अलग-अलग टीमें दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और संपत्तियों की जांच में जुटी हैं। अधिकारियों का कहना है कि तलाशी पूरी होने के बाद संपत्ति का वास्तविक मूल्य और बढ़ सकता है। सर्च में 4 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना, करीब 3 लाख रुपये नकद, इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना में 9 ठिकानों पर एक साथ छापे। सिलिकॉन सिटी स्थित करीब 1.20 करोड़ रुपये के तीन मंजिला आलीशान मकान से लेकर पीथमपुर और धार के औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर निर्माण की कई फैक्ट्रियां, व्यावसायिक कार्यालय, भूखंड और अन्य निवेश जांच के दायरे में आए हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के पुत्र, पुत्रवधू, दामाद और अन्य परिजनों के नाम से शुभम इलेक्ट्रिकल, कर्निश पावर जोन, एसएस इलेक्ट्रिकल्स, कृष्णा पावर और ए-वन इलेक्ट्रिकल जैसी फर्मों का संचालन किया जा रहा है। कई स्थानों पर नई फैक्ट्रियों का निर्माण भी जारी मिला। लोकायुक्त टीम इन निवेशों के

रिमझिम से भीगा शहर, झमाझम का इंतजार

इंदौर। शहर में पिछले कई दिनों से तेज बारिश का इंतजार लगातार बना हुआ है। सप्ताह की शुरुआत से ही आसमान पर बादलों का डेरा है, लेकिन अब तक झमाझम बारिश नहीं हो सकी है। मंगलवार सुबह से शहर के अलग-अलग हिस्सों में रिमझिम बारिश और हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जिससे मौसम में कुछ बदलाव जरूर महसूस हुआ, लेकिन लोगों को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। बीते लगभग 2 सप्ताह से लगातार बनी हुई उमस और तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिनभर चिपचिपी गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में शहरवासी जल्द तेज बारिश होने की उम्मीद लगाए हुए हैं, ताकि मौसम सुहाना हो सके और उमस से राहत मिल सके। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में नया मौसम

तंत्र सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ रही है। इसी वजह से जुलाई के अंतिम दिनों में इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी। शहर के साथ-साथ जिले की विभिन्न तहसीलों में भी मौसम ने क़ायमत ली है। महु, बेटमा, पीथमपुर, देपालपुर, हातोद और गौतमपुरा सहित आसपास के इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की गई है। इस बदलाव से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। हालांकि इंदौर शहर में अब भी सभी की निगाहें उस तेज बारिश पर टिकी हैं, जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा है।

जून माह की रैंकिंग में हीरा नगर की एसीपी मिजवानी अत्तल रही

अन्नपूर्णा दूसरे और जूनी इंदौर एसीपी तीसरे स्थान पर रहे

इंदौर। शहर में बेहतर और जनोन्मुखी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के पुलिस कमिश्नरेट ने सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के कार्यों का जून माह का मूल्यांकन जारी कर दिया है। निर्धारित मानकों पर किए गए आकलन में जून-3 की एसीपी हीरा नगर रूबीना मिजवानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे कमिश्नरेट में पहला स्थान हासिल किया है। अन्नपूर्णा एसीपी शिवेन्दु जोशी दूसरे और जूनी इंदौर एसीपी विजय चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। पुलिस कमिश्नर के मार्गदर्शन में लागू की गई इस मासिक मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य अधिकारियों के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके तहत प्रत्येक एसीपी के कार्यों की समीक्षा विभिन्न तय मापदंडों पर की जाती है।

पुलिस कमिश्नरेट के सभी 12 अनुभागों के एसीपी के कार्यों का मूल्यांकन अपराध नियंत्रण, विवेचना, लॉबित मामलों के निराकरण, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों सहित अन्य निर्धारित पैरामीटर के आधार पर किया गया।

खजुराना एसीपी रहे तीसरे – जून माह की रैंकिंग में निर्धारित मापदंडों पर सबसे कमजोर प्रदर्शन जून-2 के एसीपी खजुराना आशीष पटेल का रहा, जिसके चलते वे इस माह की रैंकिंग में अंतिम स्थान पर रहे। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की मासिक रैंकिंग से कार्यप्रणाली में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जवाबदेही मजबूत होगी और नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बता दें, पूर्व में भी हीरानगर एसीपी रैंकिंग में प्रथम रही है।

आवारा कुत्तों के झुंड से सहमे रहवासी राहगीरों और वाहन चालकों पर खतरा

इंदौर। शहर के वार्ड क्रमांक 71 के समाजवादी इंदिरा नगर में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक रहवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। क्षेत्र की गलियों और मुख्य सड़कों पर कुत्तों के झुंड खुलेआम घूम रहे हैं और राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर रहे हैं। कई मामलों में लोगों को काटने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

लगातार बढ़ रही इस समस्या से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में भय का माहौल है। रहवासियों के अनुसार सबसे अधिक पेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। कुत्तों के झुंड अचानक बाइक और स्कूटर के पीछे दौड़ पड़ते हैं, जिससे चालक घबरा जाते हैं। कई बार संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना की स्थिति बन जाती है और कुछ लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है।

क्षेत्रवासियों ने बताया कि कुछ समय पहले इसी इलाके में एक महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस घटना के बाद कार्रवाई का आश्वासन

तो मिला, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है। रहवासियों का कहना है कि शाम ढलते ही कुत्तों के झुंड अधिक आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों का घर से बाहर निकलना और लोगों का पैदल आना-जाना मुश्किल हो गया है। कई परिवारों ने बच्चों को अकेले बाहर भेजना भी बंद कर दिया है। लोगों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है और शाम के समय घर से निकलने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है।

लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि समाजवादी इंदिरा नगर में विशेष अभियान चलाकर आक्रामक आवारा कुत्तों का रेस्क्यू किया जाए। साथ ही नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया को भी तेज किया जाए, ताकि कुत्तों की संख्या नियंत्रित हो सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में वार्ड 71 की पाषंद हरप्रत कौर लुथरा ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। नगर निगम की टीम बुलाकर आवारा कुत्तों का रेस्क्यू कराया जाएगा, ताकि क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

पहले भी महिला पर हो चुका हमला, नसबंदी, टीकाकरण की मांग

के संरक्षक क्रांति चतुर्वेदी ने कहा कि गाँवों और दूरस्थ अंचलों में सीमित संसाधनों के बीच कार्य करने वाले पत्रकार ही वास्तविक अर्थों में पत्रकारिता के प्रहरी हैं। संसाधनों की कमी, आर्थिक चुनौतियों और स्थानीय दबावों के बावजूद ग्रामीण पत्रकार समाज की आवाज बनकर जनहित के मुद्दे उठाते हैं। यही पत्रकारिता की सबसे बड़ी शक्ति है।

पत्रकार लोकतंत्र की रीढ़

आलीराजपुर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की रीढ़ हैं। निष्पक्ष एवं प्रमाण आधारित पत्रकारिता शासन और समाज दोनों को जवाबदेह बनाती है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। वरिष्ठ पत्रकार तेज कुमार सेन ने प्रेक्ष संबोधन में कहा कि हनुमानजी को उनकी शक्ति का अहसास कराने जामवंत आए थे, लेकिन पत्रकारों को अपनी कलम की शक्ति स्वयं पहचानी होगी। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार जनहित के मुद्दों के निर्भीकता से उठाएगा, उसके पीछे समाज स्वयं खड़ा होगा।

स्वास्थ्य संरक्षण के लिए पहल

महासमागम का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पत्रकारों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए लिया गया। संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़वानी में एआईजे से जुड़े पत्रकारों, उनके परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों को उपचार एवं चिकित्सा सेवाओं पर 30% तक विशेष रियायत उपलब्ध कराई जाएगी। एसएमएस हॉस्पिटल, वडोदरा के डायरेक्टर डॉ मृदंग भावसार ने चिकित्सा सेवाओं पर पत्रकार जगत के लिए 30% तक सामान्य शुल्क पर विशेष छूट की घोषणा की। साथ ही अस्पताल में बिटिया के जन्म पर कोई शुल्क नहीं लेने की भी घोषणा की। राष्ट्रीय अस्थ्यश्रवण सेन और प्रदेश अध्यक्ष राकेश साहू ने दोनों अस्पतालों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एआईजे के सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह पहल पत्रकार कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।



उत्साह ने समारोह को एक भव्य राष्ट्रीय महोत्सव का स्वरूप प्रदान किया।

स्वागत उद्बोधन देते हुए एआईजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन ने देशभर से पधारे पत्रकारों एवं अतिथियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि एआईजे केवल एक संगठन नहीं, बल्कि पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार और स्वाभिमान को समर्पित राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने बताया कि आज एआईजे 24 राज्यों एवं

650 से अधिक जिलों में सक्रिय संगठनात्मक उपस्थिति के साथ पत्रकारों एवं उनके परिवारों के हितों के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। संगठन का उद्देश्य केवल सम्मान समारोह आयोजित करना नहीं, बल्कि पत्रकारों के जीवन से जुड़ी वास्तविक समस्याओं स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग के लिए व्यवस्था करना है।

नवभारत के समूह संपादक एवं एआईजे

संपादकीय

एंडी बनहैम के सामने चुनौतियां

ब्रिटेन में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच सत्तासीन लेबर पार्टी के दिग्गज नेता एंडी बनहैम ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। ब्रिटेन में पिछले एक दशक में वो देश के सातवें प्रधानमंत्री हैं। एंडी बनहैम को बीते हफ्ते शुक्रवार को ही पार्टी का नया मुखिया चुन लिया गया था। बनहैम ने उन्हें लेबर पार्टी का नेता चुने जाने को पिछले 40 वर्षों में देश की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव बताया था। नए प्रधानमंत्री के रूप में बनहैम ने देश की व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ने और सरकार का ध्यान महंगाई, बढ़ती जीवन-यापन लागत के साथ कमजोर होती सार्वजनिक सेवाओं जैसे आम लोगों के मुद्दों पर केंद्रित करने का संकल्प लिया। 56 वर्षीय बनहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहने के दौरान ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ के नाम से चर्चित रहे। बनहैम को प्रधानमंत्री बनाने की चार सप्ताह की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेबर पार्टी का नेता चुने जाने के बाद बनहैम को राज ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री कीएर स्टारमर की देश अपनी घटती लोकप्रियता के कारण उनकी ही पार्टी के सांसद उनके खिलाफ हो गए थे। नतीजतन उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बनहैम को बधाई देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह एंडी बनहैम के साथ मिलकर भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने तथा साझा विजन 2035 को आगे बढ़ाने के लिए काम करने को लेकर उत्साहित हैं। उधर सत्ता संभालते ही बनहैम ने कहा कि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगी और निर्णय लेने की ताकत देश के हर क्षेत्र तक पहुंचाएगी। आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को अधिक मजबूत सार्वजनिक नियंत्रण में लाकर उन्हें आम लोगों के लिए फिर से किफायती बनाया जाएगा। बनहैम ने अपनी सरकार को ‘ब्रिटेन के लिए सफ़्टिक ब्रेकर’ बताते हुए कहा कि उनकी सरकार देश में पिछले 40 वर्षों के सबसे बड़े बदलाव लाए करेगी। ब्रिटेन को नए राजनीतिक और आर्थिक मॉडल की जरूरत है। बहरहाल नए प्रधानमंत्री बनहैम के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। ये हैं आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधारा तथा पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में चल रहे युद्धों के बीच ब्रिटेन के हितों को संरक्षित करना। बताया जाता है कि बनहैम लंदन से ब्रिटेन के अन्य क्षेत्रों में सत्ता का बड़ा हस्तांतरण करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे असमानता कम होगी और उन पिछड़े समुदायों का पुर्नसा शांत होगा जो अब ‘रिफॉर्म यूके’ पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेबर पार्टी के सांसदों को डर था कि वे 2029 के अगले चुनाव में नाइजेर फ्राज की पार्टी ‘रिफॉर्म यूके’ से अपनी सीटें हार सकते हैं। रिफॉर्म यूके पिछले कई महीनों से ओपियनियन पोल में सबसे आगे चल रही है। हालांकि हाल के हफ्तों में अमीर दानदाताओं से फंड लेने के कारण फ्राज की पार्टी की छवि को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे बनहैम को लेबर पार्टी की स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। जहां तक राजनीतिक चुनौती की बात है तो ब्रिटेन में अगले आम चुनाव में तीन साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बनहैम को अपने वादों को जल्द से जल्द लागू करना होगा। आर्थिक विकास से जुड़े स्वतंत्र संगठन ‘इंस्टीट्यूट ऑफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट’ के कार्यकारी निदेशक नाइजेल विलकॉक ने कहा कि बनहैम ने आर्थिक विकास के एक अलग दृष्टिकोण के लिए वर्षों तक पैरवी की है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदलने की है। सबसे बड़ी चुनौती को ब्रिटेन को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की है। बनहैम भी पद पर कब तक टिकते हैं, देखना होगा।

नजरिया

संजय सक्सेना

लेखक लखनऊ निवासी
वरिष्ठ पत्रकार हैं।



दि ह्नी के जंतर-मंतर पर सोमवार को जो तस्वीर बनी, वह महज एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर नहीं थी। संसद से जंतर-मंतर तक हाथों में तख्तियां लेकर बढ़ते समाजवादी पार्टी के सांसद, पुलिस कार्रवाई से परेशान युवाओं के बीच बैठी डिंपल यादव, सरकार पर सीधे सवाल उठाती इकरा हसन और आक्रामक तेवरों में नजर आतीं प्रिया सरोज इन तीन चेहरों ने उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति की एक संभावित तस्वीर जरूर सामने रख दी है। सवाल यह नहीं है कि सोमवार के प्रदर्शन में कौन शामिल हुआ। असली सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब अपनी राजनीति को तीन अलग-अलग महिला चेहरों के जरिए नई सामाजिक और भौगोलिक जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है? सोमवार को नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर कॉन्ग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुटे थे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के सवालों पर संवाद की मांग की। इसी प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद संसद परिसर से जंतर-मंतर की ओर मार्च करते हुए पहुंचे। डिंपल यादव के साथ इकरा हसन और प्रिया सरोज की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। डिंपल यादव ने छात्रों के सवालों का समर्थन किया और कहा कि युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरों में वह आंदोलनकारियों के बीच दिखाई दीं। यही तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ी जा रही हैं। वजह साफ है। 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर की बात नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में तय समय पर होने हैं। राज्य में 403 विधानसभा सीटें हैं और इस चुनाव का असर सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा राजनीतिक मोड़ था। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 37

जंतर-मंतर की तीन तस्वीरें और राजनीतिक संदेश

पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर रह गई और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थीं और समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर रही थी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव ने राज्य की राजनीतिक जमीन पर विपक्ष के लिए नई संभावनाएं पैदा कर दीं। अब अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोकसभा चुनाव में बने सामाजिक गठजोड़ को 403 विधानसभा सीटों तक कैसे पहुंचाया जाए। यहीं डिंपल यादव की भूमिका सबसे पहले सामने आती है। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव अब सिर्फ यादव परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ा चेहरा नहीं रह गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मैनपुरी सीट पर 2,21,639 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यह जीत बताती है कि उनका व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव लगातार मजबूत हुआ है। उनका अंदाज अखिलेश यादव की आक्रामक राजनीति से अलग है। वह तीखे भाषणों की जगह संयमित भाषा, महिला मुद्दों और संवेदनशील राजनीतिक छवि के जरिए अपनी जगह बनाती हैं।

बीजेपी की राजनीति में महिला मतदाताओं का महत्व पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है। उज्ज्वला, आवास, शौचालय, राशन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी ने महिलाओं के बीच एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह महिला मतदाताओं तक अपनी सीधी पहुंच बनाए। डिंपल यादव इस चुनौती का जवाब बन सकती हैं। उनके पास पार्टी का पारंपरिक आधार है, लेकिन उनकी छवि उस आधार से आगे जाने की क्षमता भी रखती है। दूसरा चेहरा इकरा हसन का है। कैराना से लोकसभा पहुंचीं इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह की आवाज बनकर उभरी हैं। उनका राजनीतिक अंदाज सीधे सवाल पूछने वाला है। पश्चिमी यूपी में किसान, युवा, शिक्षा, रोजगार और अल्पसंख्यक राजनीति एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। यहां कोई भी राजनीतिक चेहरा तभी मजबूत होता है, जब वह स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय बहस से जोड़ सके। इकरा हसन के सामने यही अवसर है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा पहचान है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव उस पीढ़ी के बीच लड़ा जाएगा, जिसके लिए सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाएं और जातीय समीकरण राजनीतिक मुद्दा हैं। नीट विवाद,

पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवालों ने युवाओं के बीच बेचैनी पैदा की है। जंतर-मंतर का प्रदर्शन इसी असंतोष को राजनीतिक आवाज देने की कोशिश था। ऐसे मुद्दों पर इकरा हसन जैसे चेहरे सीधे युवाओं से जुड़ सकते हैं। तीसरा चेहरा प्रिया सरोज का है। मछलीशहर से सांसद प्रिया सरोज 18वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसदों में शामिल हैं। पीआरएस इंडिया के अनुसार उनकी उम्र 27 वर्ष है और लोकसभा में उनकी उपस्थिति 97 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा उनके संसदीय कामकाज को लेकर उनकी सक्रियता दिखाता है। वह सिर्फ युवा चेहरा नहीं हैं, बल्कि पूर्वांचल के उस सामाजिक और राजनीतिक भूगोल से आती हैं, जहां जातीय प्रतिनिधित्व आज भी चुनावी समीकरणों का सबसे बड़ा आधार है। अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की राजनीति का केंद्रीय संदेश बना। लेकिन कोई भी राजनीतिक फॉर्मूला केवल नारों से जमीन पर मजबूत नहीं होता। उसके लिए चेहरे चाहिए। डिंपल यादव महिला और पिछड़े वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ा सकती हैं। इकरा हसन अल्पसंख्यक और युवा राजनीति की आवाज बन सकती हैं। प्रिया सरोज वंचित और दलित-पिछड़े सामाजिक समूहों के बीच पार्टी की नई पीढ़ी का चेहरा बन सकती हैं। यही इस तिकड़ी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। यह सिर्फ तीन सांसदों का साथ नहीं है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को जोड़ने वाली संभावित राजनीतिक रेखा है। डिंपल के पास अनुभव और स्वीकार्यता है। इकरा के पास बेबाकी और युवा ऊर्जा है। प्रिया के पास नई पीढ़ी की राजनीतिक पहचान है। अगर सपा इन तीनों चेहरों को अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार सक्रिय करती है, तो यह प्रयोग पार्टी के लिए चुनावी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती को केवल इन तीन महिला सांसदों की लोकप्रियता से जोड़ना जल्दबाजी होगी। राजनीति में वायरल तस्वीरें वोट में तभी बदलती हैं, जब उनके पीछे संगठन खड़ा हो। 2024 में समाजवादी पार्टी की सफलता के बावजूद 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह अलग होगा। लोकसभा चुनाव में मुद्दों का प्रभाव व्यापक होता है, जबकि विधानसभा चुनाव में वृथ सर की मशीनों, स्थानीय उम्मीदवार और जातीय समीकरण निर्णायक होते हैं। सपा को यह साबित

करना होगा कि डिंपल, इकरा और प्रिया की लोकप्रियता सिर्फ संसद और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। बीजेपी के पास भी मजबूत संगठन, सत्ता का अनुभव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। 2022 में बीजेपी ने 403 में से 255 विधानसभा सीटें जीती थीं। इसलिए सपा के सामने सिर्फ सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की चुनौती नहीं है। उसे सत्ता के मजबूत संगठनात्मक ढांचे को चुनौती देनी होगी। यही कारण है कि तीनों महिला सांसदों की भूमिका केवल भाषणों या प्रदर्शनों से तय नहीं होगी। उन्हें गांव, कस्बे, विश्वविद्यालय, महिला समूह और युवा संगठनों के बीच लगातार दिखाई देना होगा। फिर भी जंतर-मंतर की तस्वीर को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि इस तस्वीर में तीन ऐसे राजनीतिक संदेश एक साथ दिखाई दिए, जिन पर 2027 का चुनाव टिक सकता है। युवा असंतोष, महिला राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक प्रतिनिधित्व। अगर इन तीनों मुद्दों को सपा लगातार जमीन पर ले जावे है, तो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला केवल जातीय समीकरण नहीं रहेगा, बल्कि नए चेहरों और नए मुद्दों के साथ एक व्यापक राजनीतिक अभियान बन सकता है।

डिंपल यादव की संवेदनशीलता, इकरा हसन की बेबाकी और प्रिया सरोज की युवा ऊर्जा फिलहाल एक राजनीतिक संभावना है। इसे चुनावी ताकत में बदलना समाजवादी पार्टी की रणनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सोमवार को जंतर-मंतर पर जो तस्वीर बनी, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या 2027 में बीजेपी के सामने अखिलेश यादव का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ पीडीए नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ी यह नई महिला राजनीतिक तिकड़ी भी होगी? उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं। गठबंधन बदलेंगे, उम्मीदवार बदलेंगे, मुद्दे बदलेंगे और चुनावी नारों का रंग भी बदलेगा। लेकिन राजनीति में कुछ तस्वीरें समय से पहले संकेत दे देती हैं। जंतर-मंतर की वह तस्वीर भी शायद ऐसी ही तस्वीर है। अगर समाजवादी पार्टी ने इन तीनों चेहरों को सिर्फ संसद की सीमाओं में बंद नहीं रखा और उन्हें उत्तर प्रदेश की जमीन पर लगातार उतारा, तो डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए सिर्फ विपक्षी सांसद नहीं, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक मोर्चा बन सकती हैं, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

प्रतिभा पलायन

अरूण कुमार उनायक

लेखक समाजसेवी हैं।



स्व तंत्र भारत के सामने वैज्ञानिक प्रतिभाओं का अभाव सबसे बड़ी चुनौती थी। नेहरू ने विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को यह भरोसा दिलाया कि देश उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप अवसर देगा। परिणामस्वरूप अनेक प्रतिभाएँ लौटीं और भारत के वैज्ञानिक भविष्य की नींव रखी। प्रो. यू. आर. राव ने अमेरिका का शोध-कार्यार छोड़ भारत लौटकर उपग्रह कार्यक्रम को दिशा दी और इसरो को विश्वसनीय संस्थान बनाया। लगभग सात दशक बाद परिदृश्य चिंतानुक्रम रूप से बदलता दिखाई देता है। कभी जिस इसरो ने विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को स्वदेश लौटने के लिए प्रेरित किया था, आज वही संगठन अपने अनुभवी वैज्ञानिकों को संस्थान में बनाए रखने की चुनौती से जूझ रहा है। हाल के महीनों में इसरो के लगभग एक सौ से अधिक वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के त्यागपत्रों ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या भारत फिर से अपनी वैज्ञानिक पूँजी खोने लगा है? क्या यह केवल सामान्य कर्मचारी परिवर्तन है, या इसके पीछे विज्ञान प्रशासन और नौकरशाही की संरचनात्मक समस्या है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के सबसे महत्वाकांक्षी दौर में प्रवेश कर चुका है। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, चंद्रयान-4, मंगलयान-2, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, अगली पीढ़ी के संचार एवं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह- इन परियोजनाओं की सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि अनुभवी वैज्ञानिकों पर निर्भर है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का अनुभव और संस्थागत ज्ञान तत्काल प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। डॉ. जितेन्द्र सिंह का यह कथन- ‘बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग आते हैं’—सामान्य प्रशासनिक दृष्टि से भले स्वाभाविक लगे, किंतु अंतरिक्ष विज्ञान में वैज्ञानिक विशेषज्ञता का

क्या भारत अपनी वैज्ञानिक पूँजी सहेज पाएगा?

हाल के महीनों में इसरो के लगभग एक सौ से अधिक वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के त्यागपत्रों ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या भारत फिर से अपनी वैज्ञानिक पूँजी खोने लगा है? क्या यह केवल सामान्य कर्मचारी परिवर्तन है, या इसके पीछे विज्ञान प्रशासन और नौकरशाही की संरचनात्मक समस्या है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के सबसे महत्वाकांक्षी दौर में प्रवेश कर चुका है। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, चंद्रयान-4, मंगलयान-2, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, अगली पीढ़ी के संचार एवं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह— इन परियोजनाओं की सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि अनुभवी वैज्ञानिकों पर निर्भर है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का अनुभव और संस्थागत ज्ञान तत्काल प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। डॉ. जितेन्द्र सिंह का यह कथन- ‘बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग आते हैं’—सामान्य प्रशासनिक दृष्टि से भले स्वाभाविक लगे, किंतु अंतरिक्ष विज्ञान में वैज्ञानिक विशेषज्ञता का महत्व इससे कहीं अधिक है। इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संतुलित रही, फिर भी दोनों वक्तव्य त्यागपत्रों के मूल कारणों पर मौन हैं।

वैज्ञानिकों के बढ़ते त्यागपत्रों के बीच 14 जुलाई 2026 को अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान सहित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिकों के त्यागपत्रों पर अंतिम निर्णय का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। यदि स्थिति सामान्य होती, तो ऐसी असाधारण व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्पष्ट है कि प्रशासनिक आश्वसनों से अधिक आवश्यकता इसके वास्तविक कारणों की निष्पक्ष समीक्षा की है।

निजी अंतरिक्ष उद्योग का विस्तार वैज्ञानिकों के त्यागपत्रों का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने और 2023 की भारतीय अंतरिक्ष नीति लागू होने के बाद देश में चार सौ से अधिक अन्तरिक्ष स्टार्टअप विकसित हुए हैं। बेहतर वेतन, नेतृत्व के अवसर, स्टॉक विकल्प और अपेक्षाकृत तेज निर्णय-प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से अनुभवी वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार का सकारात्मक संकेत भी माना जा सकता है। किंतु प्रतीक्षा पलायन को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यदि इसके पीछे संस्थागत असंतोष, वैज्ञानिक स्वायत्तता में कमी, निर्णय-प्रक्रिया में घटती भागीदारी

और सीमित कैरियर अवसर जैसे कारण भी हैं, तो यह भारत की विज्ञान नीति के लिए गंभीर चेतावनी है। भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों में लंबे समय से यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि अनेक महत्वपूर्ण तकनीकी निर्णयों में वैज्ञानिक नेतृत्व की अपेक्षा सामान्य प्रशासनिक तंत्र का प्रभाव अधिक होता जा रहा है। विज्ञान और अंतरिक्ष जैसे अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में भी कई बार अंतिम निर्णय ऐसे अधिकारियों के हाथों में होता है, जिनकी विशेषज्ञता प्रशासनिक प्रबंधन में होती है, वैज्ञानिक अनुसंधान में नहीं। फलस्वरूप वर्षों के शोध और तकनीकी अनुभव से तैयार वैज्ञानिक अनुसंधान फाइलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अपना मूल स्वरूप खो बैठती है। निस्संदेह किसी भी संस्थान के सुचारु संचालन के लिए प्रशासन अनिवार्य है, किंतु जब वह वैज्ञानिक विवेक का विकल्प बनने लगे, तो शोध, नवाचार और निर्णय-प्रक्रिया प्रभावित होना स्वाभाविक है। प्रश्न यह नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी सक्षम हैं या नहीं, बल्कि यह है कि अत्यधिक विशिष्ट वैज्ञानिक निर्णयों में अंतिम प्रार्थमिकता वैज्ञानिक विशेषज्ञता को मिले या सामान्य प्रशासनिक दृष्टिकोण को। विज्ञान प्रशासन का उद्देश्य वैज्ञानिक निर्णयों को सुगम बनाना होना चाहिए, उनका विकल्प बनना नहीं। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की जाकसा जैसी संस्थाओं में वैज्ञानिकों का उद्योग, विश्वविद्यालय

और सरकारी अनुसंधान संस्थानों के बीच आवागमन सामान्य है। इस गतिशीलता को प्रतिभा पलायन नहीं, बल्कि ज्ञान परिसंचरण माना जाता है। चीन ने विदेशों में प्रशिक्षित अपने वैज्ञानिकों को योजनाबद्ध ढंग से स्वदेश लौटाया और उन्हें विश्वस्तरीय अनुसंधान वातावरण उपलब्ध कराया। यही नीति आज उसकी वैज्ञानिक प्रगति की प्रमुख आधारशिलाओं में से एक है। इसके विपरीत भारत अब तक विदेशों में कार्यरत अपनी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को बड़े पैमाने पर वापस लाने की कोई प्रभावी और दीर्घकालिक नीति विकसित नहीं कर पाया है। यद्यपि समय-समय पर रामानुजन फेलोशिप, रामालिंगास्वामी री-एंट्री फेलोशिप, वज्र तथा हाल में वैभव जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं, जिनसे अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भारतीय संस्थानों से जुड़े भी हैं, किंतु इन्हें अभी तक व्यापक राष्ट्रीय प्रतिभा-वापसी नीति का रूप नहीं मिल सका है।

त्यागपत्रों पर प्रशासनिक रोक अल्पकालिक समाधान हो सकती है, किंतु दीर्घकालीन नहीं। प्रतिभा को आदेश से रोका जा सकता है, लेकिन उत्कृष्टता केवल विश्वास और सम्मान से ही अर्जित की जा सकती है। भारत के सामने बड़ा प्रश्न यह है कि पिछले एक दशक में विदेशों में कार्यरत कितने भारतीय वैज्ञानिक स्थायी रूप से वापस लौटे? क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति है जो वैश्विक भारतीय

वैज्ञानिक समुदाय को पुनः देश के अनुसंधान संस्थानों से जोड़ सके? प्रतिभा संरक्षण के साथ-साथ प्रतिभा वापसी को भी राष्ट्रीय विज्ञान नीति का अभिन्न भाग बनाना होगा। इसरो का संकेत केवल एक संस्थान का संकेत नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक नीति की परीक्षा है। यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखता है, तो उसे केवल रॉकेट, उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन नहीं बनाने होंगे; उसे ऐसे संस्थान भी बनाने होंगे जहाँ वैज्ञानिक सम्मान, स्वायत्तता और सृजनात्मक स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहें। स्वतंत्र भारत ने कभी यू. आर. राव जैसी प्रतिभाओं को स्वदेश लौटने का विश्वास दिलाया था; आज आवश्यकता उस विश्वास को पुनः स्थापित करने की है। राष्ट्र केवल प्रक्षेपण यानों से अंतरिक्ष शक्ति नहीं बनते, वे उन वैज्ञानिकों के विश्वास से बनते हैं जो अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अपने ही देश को समर्पित करने का निर्णय लेते हैं। विज्ञान में प्रतिभा पलायन केवल मानव संसाधन का नुकसान नहीं होता; उसके साथ वर्षों का संस्थागत अनुभव, तकनीकी स्मृति और भविष्य की अनेक संभावनाएँ भी चली जाती हैं। यदि भारत 21वीं सदी में वैज्ञानिक महाशक्ति बनना चाहता है, तो उसे वैज्ञानिकों को रोकने की नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहाँ प्रतिभाएँ लौटना भी चाहें और जीवन भर योगदान देना भी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए
उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16,
अल्फा इंडस्ट्रियल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-
453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी,
बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक

हेमंत पाल

प्रबंध संपादक

रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा।)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं।
इन्हें समाचार पत्र का रहस्य होना आवश्यक नहीं है।

खंगर

जवाहर चौधरी

लेखक खंगरकार हैं।



चु नाव के चार दिन किसी के लिए कुछ भी हों राजनीति वालों के लिए मानो बेटी का ससुराल होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति सामने पड़े फ़ट्ट से झुक जाओ, चट्ट से चरण छू लो या फिर बनता हो तो लपक के हग कर लो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग ज्यादा प्रसिद्ध हुआ या हग यह देखने वाली बात है। हग दो तरफ़ा क्रिया होती है इसलिए इज्जत भी रह जाती है। पता ही नहीं पड़ता कि कौन किसको कर रहा है। दोनों सीना भिड़ाए एक-दूसरे कि पीठ थपकाते हैं, मानो आशीर्वाद दे रहे हों। दोनों अपना बड़प्पन कवम कर लेते हैं। इसलिए जब भी जरूरत महसूस हो तो झपट कर हग करें और ससम्मान खुश रहें। यह चुनाव के समय की स्थिति है। सामान्य वक्तों में बशीर बद का कहना सही है.. ‘कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से; ये नये मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो।’

माना जाता है कि लोकतंत्र में चुनाव हुआ व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदार होता है लेकिन हकीकत यह है कि वह किसीको जवाब नहीं देता है। अघोषित सूत्र यह है कि जो सबके प्रति जवाबदार हो वह किसी के प्रति जवाबदार

हमें बारूद-युद्ध की नहीं हग-युद्ध की जरूरत

नहीं होता। अगर वह ठान ले कि जवाब नहीं देना है तो कोई भले ही अनशन पर बैठ जाए, उसका मुंह नहीं खुलवा सकता है। जनसंख्या जब करोड़ों में हो तो वादे

करना चाहिए। पिछले वादों पर नए वादों की धूल डालना आसान होता है। तमाम वादे हों तो लोग भ्रमित रहते हैं। नए वादों के नीचे पुराने वादे दफन हो जाते हैं। धीरे-धीरे जनता वादों और नेताओं से ऊब कर भजन कीर्तन में लग जाती है। धर्म को अफीम भी कहा गया है। अफीम का

नशा सात्विक होता है। इसमें आदमी संसार में रह कर भी संसार का नहीं होता है। राजनीति वाले इस बात की गहराई को समझते हैं।

दुनियावारी का ज्ञान रखने वाले हमारे मित्र सरदार पहाड़सिंह एक ही बात कहते हैं कि- ‘राजनीति बड़ी कुत्ती-चीज होती है जी’। अवश्य होती होगी, अभी तक किसी शहरी-गैरशहरी कुत्ती-चीज ने आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। आज की राजनीति का ऐसा है कि वह पड़े और प्राइज टैग वाली होती जा रही है। जिन्हें आपत्ति दर्ज

कराना होती है वे अक्सर दुम हिलाने लग जाते हैं। लोग उनके नक्शेकदम अपनी पार्टियाँ व निष्ठाएँ तक बदलने में देर नहीं करते हैं। वैश्विक राजनीति में भी इसी प्रकार की कुत्ती-अदाएं दिखाई देती है। कौन कब गुपुने लगेगा, कब किस पर झपट पड़ेगा कुछ कहा जा सकता है ?

दुनिया देख रही है कि शांति का पुस्कार नहीं मिले तो माय-फ़्रेड किस तरह सफ़ेद कबूतर कि गर्दन मरोड़ कर मिसाइल दागने लगता है।

असल बात यह है कि दुनिया में शांति कायम रखना है तो बारूद-युद्ध नहीं हग-युद्ध की जरूरत है। जिसने आगे बढ़ कर हग किया उसे फट्ट से उतना ही हग मिला। सोचिए अमेरिकी और ईरानी लड़कें दनादन हग करें तो अखबारों की हेडलाइन इत्र से छपने लगेंगी। देसी राजनीतिक संबंधों में भी हग एक शोध का विषय हो सकता है। जो हग के कीड़े हैं वे हग की ताकत जानते हैं। अपना देसी वाला हग थोड़ा अलग होता है। बाजार को हग का मुनाफा मालूम है। सुन है एक लापरस्ट शो वाला हग हग के अरबपति और नंबर वन हो गया है। समय का संकेत है कि ‘गले पड़ के’ धंधा करो। कंपटीशन बहुत है। संस्थान सोच रहे हैं कि अब रिसेप्शनिस्ट के साथ-साथ ह्वाीस्ट भी रखना पड़ेगा। रिसर्च वाले कह रहे हैं कि मेल-फीमेल दोनों होरियंस की मांग में जबरदस्त उछाल आने वाला है। बाजार और राजनीति के उस्ूलों में ज्यादा अंतर नहीं है। धंधों में काम अलग-अलग हो सकता है लेकिन नियत एक ही होती है। तो चलिए, निकलिए बाहर, हग-मार्केट की ओर चलते हैं।

पुण्य स्मरण

बृजमोहन श्रीवास्तव

राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनलिरट कांग्रेस पार्टी



22 जुलाई को पहली बार ऐसा अवसर आया है जब अजित दादा पवार हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनका जन्मदिवस हमें उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और राजनीतिक दृष्टि को पुनः स्मरण करने का अवसर देता है। किसी भी सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके पदों या उपलब्धियों से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उसने कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार नेतृत्व किया और अपने संगठन को कौन-सी दिशा दी। मेरे लिए अजित दादा केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने संवेदनशीलता, स्पष्टवादिता, प्रशासनिक दक्षता और संगठनात्मक लोकतंत्र को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाया। मैंने उन्हें अनेक अवसरों पर निकट से देखा और पाया कि वे निर्णय लेने से कभी नहीं डरते थे, किंतु हर महत्वपूर्ण निर्णय को जनता और संगठन की सामूहिक सहमति से जोड़कर देखते थे। यही गुण उन्हें समकालीन राजनीति में विशिष्ट बनाता था। भारतीय राजनीति में संकट का समय किसी भी नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा होता है। जब राजनीतिक असहमति, कानूनी विवाद और मीडिया की चुनौतियाँ एक साथ सामने हों, तब अधिकांश नेता या तो रक्षात्मक हो जाते हैं अथवा निर्णयों को सीमित दायरे में समेट देते हैं। किंतु अजित दादा ने विपरीत परिस्थितियों में भी संगठनात्मक लोकतंत्र पर अपना विश्वास बनाए रखा। इस संदर्भ में 30 नवम्बर 2023 को कर्जत में आयोजित राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यकारी समिति (एनसीडब्ल्यूसी) और महासभा की बैठक विशेष महत्व रखती है। उस समय पार्टी एक साथ राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर संघर्ष कर रही थी। संगठन निर्भाजित हो चुका था, चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। फलस्वरूप कार्यकर्ताओं के बीच स्वाभाविक रूप से असमंजस का वातावरण था।

सरोकार

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।



हाल के महीनों में वियतनाम द्वारा नकली लकजरी सामानों के विरुद्ध चलाया गया व्यापक अभियान केवल कानून-व्यवस्था की कार्रवाई नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक व्यापार की नई वास्तविकता का संकेत भी है। अमेरिका लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि वियतनाम नकली ब्रांडेड वस्तुओं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और चीनी उत्पादों के पुनः निर्यात का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिकी दबाव और ऊँचे आयात शुल्क की आशंकाओं के बीच वियतनाम सरकार ने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की। हो ची मिन्ह सिटी सहित अनेक स्थानों पर हजारों नकली उत्पाद जब्त किए गए और ऑनलाइन बिक्री नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा गया। वियतनाम अकेला नहीं है। हाल के वर्षों में अमेरिका, हांगकांग, थाईलैंड और कई अन्य देशों ने भी नकली लकजरी वस्तुओं के विरुद्ध अभियान तेज किए हैं। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि नकली सामानों का कारोबार अब केवल कुछ फुटपाथी दुकानों तक सीमित नहीं रहा। यह संगठित अपराध, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा बहु-अरब डॉलर का वैश्विक कारोबार बन चुका है।

आज किसी भी बड़े शहर के बाजार, पर्यटन स्थल या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ‘फर्स्ट कॉपी’, ‘मिरर कॉपी’ और ‘एएए कॉपी’ जैसे शब्द आम हो चुके हैं। महंगे ब्रांडों के जूते, बैग, घड़ियाँ, कपड़े, इत्र और चश्मे उनकी वास्तविक कीमत के छोटे से हिस्से में उपलब्ध मिल जाते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि अधिकांश खरीदार जानते हैं कि वे नकली वस्तु खरीद रहे हैं, फिर

राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।



विश्व में प्रत्येक राष्ट्र का अपना-अपना राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज ही उसकी मर्यादा और अस्मिता से जुड़ा होता है लेकिन इस मायने में हमारा राष्ट्र ध्वज ‘तिरंगा’ अन्य राष्ट्र ध्वजों के मुकाबले अनेक विशेषताएँ धारण किए हुए है। चूंकि अंग्रेजों से भारत की मिली आजादी के चंद दिन पहले ही 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान भारतीय तिरंगे को देश के आधिकारिक ध्वज के रूप में अपनाया था, इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष 22 जुलाई को ‘राष्ट्रीय ध्वज दिवस’ मनाया जाता है। आधिकारिक रूप में तिरंगे को अपनाने के बाद से यह देश की एकता, साहस, और आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत की सम्प्रभु राष्ट्र बनने की यात्रा का स्मरण कराता है। तिरंगा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता के लिए इसके कठिन संघर्ष और एकजुट एवं समृद्ध राष्ट्र के लिए अपने लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हमारा राष्ट्र ध्वज न केवल राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा, गौरव, शक्ति, आदर्श और आकांक्षाओं का प्रतीक है बल्कि समूचे विश्व को त्याग की भावना एवं शांति का संदेश भी देता है। यह हमारी स्वतंत्रता का भी प्रतीक है क्योंकि आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को एकजुट करने में इसकी बहुत अहम भूमिका रही। तिरंगे ने ही भारतवासियों को एकता और भाईचारे का संदेश देकर उन्हें एक सूत्र में पिरोकर अंग्रेजों से लोहा लेने को प्रेरित किया था। तब क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान अपने प्राणों से भी बढ़कर होता था, इसीलिए अंग्रेजों की लाठियाँ व गोलियाँ खाते हुए भी उन्होंने इसे कभी झुकने नहीं दिया।

वीथिका

अजित दादा पवार : लोकतांत्रिक नेतृत्व की अविस्मरणीय विरासत

मेरे लिए अजित दादा केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने संवेदनशीलता, स्पष्टवादिता, प्रशासनिक दक्षता और संगठनात्मक लोकतंत्र को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाया। मैंने उन्हें अनेक अवसरों पर निकट से देखा और पाया कि वे निर्णय लेने से कभी नहीं डरते थे, किंतु हर महत्वपूर्ण निर्णय को जनता और संगठन की सामूहिक सहमति से जोड़कर देखते थे। यही गुण उन्हें समकालीन राजनीति में विशिष्ट बनाता था। भारतीय राजनीति में संकट का समय किसी भी नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा होता है। जब राजनीतिक असहमति, कानूनी विवाद और मीडिया की चुनौतियाँ एक साथ सामने हों, तब अधिकांश नेता या तो रक्षात्मक हो जाते हैं अथवा निर्णयों को सीमित दायरे में समेट देते हैं। किंतु अजित दादा ने विपरीत परिस्थितियों में भी संगठनात्मक लोकतंत्र पर अपना विश्वास बनाए रखा। इस संदर्भ में 30 नवम्बर 2023 को कर्जत में आयोजित राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यकारी समिति (एनसीडब्ल्यूसी) और महासभा की बैठक विशेष महत्व रखती है। उस समय पार्टी एक साथ राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर संघर्ष कर रही थी।



संगठन की सामूहिक शक्ति से किया जाएगा। उनका यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने न्यायालय, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को लोकतंत्र का अभिन्न अंग माना। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि संस्थाएँ महत्वहीन हैं; बल्कि उनका विश्वास था कि

राजनीतिक और संगठनात्मक वैधता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई उनके लिए केवल एक कानूनी विवाद नहीं थी, बल्कि संगठन की लोकतांत्रिक स्वीकृति की परीक्षा भी थी।

30 नवम्बर 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अजीत दादा का पाँच साल के लिये निर्वाचन तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों का पाँच वर्षों के लिए निर्वाचन भी इसी व्यापक सोच का हिस्सा था। यह केवल संगठनात्मक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उस समय चल रहे राजनीतिक और कानूनी संघर्ष के बीच पार्टी को स्पष्ट दिशा देने का प्रयास था। उस दिन कर्जत में दिया गया अजित दादा का भाषण समय की सीमाओं से परे एक राजनीतिक दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए। उसमें केवल तत्कालीन परिस्थितियों का उतर नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि किसी भी लोकतांत्रिक संगठन को संकट की घड़ी में किस प्रकार कार्य करना चाहिए। उनका विश्वास था कि पारदर्शिता से संगठन कमजोर नहीं होता, बल्कि और अधिक मजबूत बनता है। खुली चर्चा असहमति को जन्म नहीं देती, बल्कि विश्वास को मजबूत करती है।

आज जब भारतीय राजनीति में दलों के आंतरिक लोकतंत्र पर निरंतर बहस होती रहती है, तब अजित दादा

की कार्यशैली हमें यह स्मरण कराती है कि संगठन की स्थायी शक्ति केवल चुनावी सफलता से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के विश्वास से निर्मित होती है। यही विश्वास किसी भी राजनीतिक दल को लंबे समय तक जीवंत बनाए रखता है। अजित दादा पवार के नेतृत्व का सबसे बड़ा संदेश यही था कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि संस्थाओं, संविधान और संगठनात्मक मूल्यों के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का भी माध्यम है। नेतृत्व का अर्थ केवल निर्णय लेना नहीं, बल्कि लोगों को निर्णय प्रक्रिया का सहभागी बनाना है। आज उनके जन्मदिवस पर उन्हें स्मरण करना केवल श्रद्धांजलि देना नहीं है। यह उस लोकतांत्रिक दृष्टि को याद करने का अवसर भी है, जिसमें कार्यकर्ता सर्वोच्च है, संवाद सबसे बड़ी शक्ति है और कानून तथा संविधान संघर्ष के सबसे विश्वसनीय आधार हैं।

यदि हम वास्तव में अजित दादा पवार को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी सीख को आत्मसात करना होगा—संगठन विश्वास से चलता है, भय से नहीं; लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है, गोपनीयता से नहीं; और नेतृत्व वही है जो सबसे कठिन समय में भी चट्टान की तरह अडिग रहकर अपने साथियों का विश्वास बनाए रखे। इसी संकल्प के साथ हम सब उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

सस्ते सौदे की असली कीमत

भी उन्हें कोई अपराधबोध नहीं होता। उनके लिए यह कम कीमत में प्रतिष्ठा का अनुभव खरीदने जैसा सौदा है। यही इस समस्या की सबसे बड़ी चुनौती है। नकली सामानों का बाजार केवल आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान के कारण भी फल-फूल रहा है। लकजरी ब्रांड आज उपयोगिता से अधिक सामाजिक पहचान का माध्यम बन चुके हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तीव्र किया है। तस्वीरों और वीडियो की दुनिया में वस्तु की गुणवत्ता से अधिक उसका लोگو दिखाई देता है। ऐसे में यदि कम कीमत पर वही बाहरी स्वरूप मिल जाए तो अनेक उपभोक्ता उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करते।

नकली उत्पाद बनाने वालों के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी कारोबार है। उन्हें न अनुसंधान पर खर्च करना पड़ता है, न डिजाइन, गुणवत्ता परीक्षण, विज्ञापन या ब्रांड निर्माण पर। वे केवल प्रसिद्ध ब्रांड की पहचान का अनुचित लाभ उठाकर कम लागत में भारी मुनाफा अर्जित करते हैं। यही कारण है कि यूरोप, अमेरिका, चीन, तुर्किये, दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत सहित अनेक देशों में यह समानांतर बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली के पालिका बाजार से लेकर मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत और जयपुर जैसे शहरों तक नकली

ब्रांडों का कारोबार वर्षों से चलता आ रहा है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इसे और व्यापक बना दिया है। सोशल मीडिया और छोटे ई-कॉमर्स माध्यमों के जरिए नकली उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुँच रहे हैं। कई बार उपभोक्ता स्वयं भी यह पहचान नहीं पाता कि उसने असली वस्तु खरीदी है या उसकी नकल। इसका दूसरा पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मूल ब्रांड बनाने वाली

खराब गुणवत्ता वाले नकली उत्पाद को असली समझ ले, तो उसके मन में ब्रांड की छवि भी धूमिल हो सकती है। दीर्घकाल में यह नवाचार और अनुसंधान पर निवेश के उत्साह को भी प्रभावित करता है।

लेकिन इसका प्रभाव केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहता। नकली वस्तुओं के कारण सरकारों को कर राजस्व का नुकसान होता है, वैध उद्योगों में रोजगार प्रभावित होता है और संगठित अपराध को आर्थिक आधार मिलता है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों, विद्युत उपकरणों और वाहन के पुर्जों जैसे क्षेत्रों में नकली उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

हालाँकि इस बहस का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ लकजरी ब्रांड अपनी वास्तविक उत्पादन लागत की तुलना में अत्यधिक

ऊँचे मूल्य वसूलते हैं। उपभोक्ता का बड़ा भुगतान उत्पाद की उपयोगिता के बजाय उसकी ब्रांड छवि और विशिष्टता के लिए होता है। परिणामस्वरूप अनेक लोग यह महसूस करते हैं कि वे केवल नाम के लिए अत्यधिक कीमत चुका रहे हैं। यह धारणा भी नकली उत्पादों की मांग को बढ़ाती है। इसलिए समस्या केवल

अवैध कारोबार की नहीं, बल्कि अत्यधिक महंगी उपभोक्ता संस्कृति की भी है।

स्पष्ट है कि इस चुनौती का समाधान केवल छापेमारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकता। बौद्धिक संपदा कानूनों का प्रभावी पालन, सीमा शुल्क एजेंसियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली उत्पादों की त्वरित पहचान और हटाने की व्यवस्था तथा आधुनिक डिजिटल प्रमाणिकरण तकनीकों का व्यापक उपयोग आवश्यक होगा। क्यूआर कोड, ब्लॉकचेन आधारित सत्यापन और डिजिटल प्रमाणपत्र जैसी तकनीकें इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इसके साथ ही ब्रांड कंपनियों को भी आत्ममंथन करना होगा। यदि वे बेहतर गुणवत्ता के साथ अपेक्षाकृत सुलभ मूल्य वाली उत्पाद श्रृंखलाएँ विकसित करें, तो नकली बाजार का आकर्षण स्वाभाविक रूप से घट सकता है। भारत जैसे देशों में स्थानीय गुणवत्ता आधारित ब्रांडों को प्रोत्साहन देकर उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और किफायती विकल्प उपलब्ध कराना भी दीर्घकालिक समाधान का हिस्सा होना चाहिए।

दरअसल नकली लकजरी वस्तुओं का कारोबार केवल सस्ती खरीदारी का प्रश्न नहीं है। यह उपभोक्ता मनोविज्ञान, सामाजिक प्रतिष्ठा, वैश्विक व्यापार, कानून, नवाचार और नैतिकता के जटिल अंतर्संबंधों का परिणाम है। जब तक कम कीमत में प्रतिष्ठा पाने की मानसिकता बनी रहेगी, तब तक नकली बाजार भी किसी न किसी रूप में जीवित रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि सरकारें प्रभावी कानून लागू करें, कंपनियाँ मूल्य और उपलब्धता के बीच संतुलन स्थापित करें तथा उपभोक्ता भी मौलिकता और गुणवत्ता के महत्व को समझें। स्वस्थ और निष्पक्ष बाजार व्यवस्था की रक्षा का यही सबसे टिकाऊ मार्ग है।

संविधान और संप्रभु भारत का अमर प्रतीक तिरंगा

राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत की सम्प्रभु राष्ट्र बनने की यात्रा का स्मरण कराता है। तिरंगा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता के लिए इसके कठिन संघर्ष और एकजुट एवं समृद्ध राष्ट्र के लिए अपने लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हमारा राष्ट्र ध्वज न केवल राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा, गौरव, शक्ति, आदर्श और आकांक्षाओं का प्रतीक है बल्कि समूचे विश्व को त्याग की भावना एवं शांति का संदेश भी देता है। यह हमारी स्वतंत्रता का भी प्रतीक है क्योंकि आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को एकजुट करने में इसकी बहुत अहम भूमिका रही। तिरंगे ने ही भारतवासियों को एकता और भाईचारे का संदेश देकर उन्हें एक सूत्र में पिरोकर अंग्रेजों से लोहा लेने को प्रेरित किया था।

तीन रंगों की पट्टियों वाले राष्ट्रीय ध्वज की सबसे ऊपर की केसरिया रंग की पट्टी त्याग, बल और पौरुष की प्रतीक है जबकि बीच वाली सफेद पट्टी शांति और सत्य की प्रतीक है और सबसे नीचे की हरे रंग की पट्टी हरियाली, समृद्धि एवं सम्यन्ता की प्रतीक है। झंडे के बीचों-बीच सफेद पट्टी में स्थित गहरे नीले रंग का अशोक चक्र आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 24 तीलियों वाला अशोक चक्र देश की प्रगति, राष्ट्र के कानून और धर्म के पहिये का प्रतीक है। डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में कहें तो जो लोग इस ध्वज के नीचे कार्य करेंगे, उन्हें सत्य और सदाचार के सिद्धांतों का पालन करना होगा। राष्ट्र ध्वज के नीचे कार्य करने वालों से उनका तात्पर्य सरकारों और नौकरशाहों से था। राष्ट्र कोकिला सरोजिनी नायडू ने भी राष्ट्र ध्वज की महत्ता का उल्लेख करते हुए संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज का प्रस्ताव पेश करते समय 22 जुलाई 1947 को कहा था कि नए भारत के सभी नागरिकों को इस राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करना होगा और इसके नीचे कोई छोटा-बड़ा नहीं होगा।

राष्ट्र ध्वज का सफर 7 अगस्त 1906 को आरंभ हुआ था। हरे, पीले और लाल रंग की तीन पट्टियों से बना यह राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान में फहराया गया था। उस ध्वज पर ऊपर की हरी पट्टी पर

एक ही पंक्ति में सफेद रंग के आठ कमल अंकित थे जबकि बीच वाली पीली पट्टी पर देवनागरी में गहरे नीले रंग से वंदेमातरम् लिखा था और नीचे की लाल पट्टी पर बायें और एक सफेद सूर्य और दायें और एक-एक सफेद चन्द्रमा और तारा अंकित थे। ‘भारत का झंडा’ नामक यह ध्वज हालांकि भारत के सभी धर्मों, सम्प्रदायों और साम्प्रदायिक सद्भावना को मदेनजर रखते हुए तैयार किया गया था लेकिन यह ध्वज सर्वमान्य नहीं हो पाया। 1917 में डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा ‘होमरूल आन्दोलन’ चलाया गया था। उस समय एक नया राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया, जिसमें लाल और हरे रंग की एक के बाद एक कुल 9 समानान्तर और तिरछी पट्टियाँ थीं। उस ध्वज के बीचों-बीच 7 तारे थे और एक कोने में चांद व तारा अंकित थे जबकि उसके ऊपरी बायें कोने में ‘यूनियन जैक’ का चित्र (झंडे का चौथाई भाग) बनाया गया था। झंडे में यूनियन जैक के इस चित्र को सम्मिलित किए जाने के कारण ही यह अधिकांश लोगों द्वारा नापसंद कर दिया गया क्योंकि इस चित्र को राष्ट्रीय ध्वज में स्थान देने का अर्थ यही माना गया कि भारतीय समाज की ब्रिटिश सम्प्रभुता के प्रति स्वीकृति है। तब एक ऐसे ध्वज की आवश्यकता महसूस की गई, जो प्रत्येक धर्म, सम्प्रदाय और विचारधाराओं के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के

साथ देशवासियों के लिए जीवन-मरण का प्रतीक भी बन सके। 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के पिंगली वैकैया नामक क्रांतिकारी युवक ने महात्मा गांधी को एक ऐसा ध्वज भेंट किया, जिसमें लाल व हरे रंग की केवल दो पट्टियाँ थीं लेकिन पंजाब के एक बुजुर्ग नेता रायजदा पंडित हंसराज ने गांधी जी को सुझाव दिया कि इस ध्वज में चरखे को भी अंकित किया जाए और तब गांधी जी ने यह सुझाव स्वीकारते हुए हिन्दुओं के लिए केसरिया रंग, मुस्लिमों के लिए हरा रंग तथा अन्य सम्प्रदायों के लिए ध्वज में सफेद रंग को भी शामिल किया। 31 दिसम्बर 1929 को रावी नदी के तट पर इसी तिरंगे को फहराते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। हालाँकि बहुत से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज को जातियों व धर्म-सम्प्रदाय से जोड़ना उचित नहीं लगा, अतः 1931 में राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप के निर्धारण के लिए कराची कांग्रेस ने 7 व्यक्तियों की एक समिति बनाई और समिति ने एक ही रंग (केसरिया) के ध्वज में नीचे बायें और लाल रंग के चरखे का चिन्ह अंकित करने का सुझाव दिया, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात् पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई और उस बैठक में तिरंगे ध्वज को ही बीच की सफेद पट्टी में चरखे सहित

मान्यता प्रदान की गई और उस निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह रही कि तीनों पट्टियों के रंगों को धर्म-सम्प्रदायों से न जोड़कर उनके गुणों के आधार पर ही स्वीकार किया गया। इस ध्वज का आकार लम्बाई और चौड़ाई में 3:2 रखा गया।

1924 में आजादी के लिए संघर्षरत श्यामलाल गुप्त ‘पाषंद’ ने झंडा गीत ‘‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा’’ की रचना की और महात्मा गांधी ने उस गीत के दूसरे और तीसरे भाग को हटाकर उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। वह गीत पहली बार कानपुर में 1925 में कांग्रेस सम्मेलन में सामूहिक रूप से गाया गया। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसे एक लाख लोगों के साथ गाया और देखते ही देखते यह गीत क्रांतिकारियों का सबसे लोकप्रिय गीत बन गया। चाहे कांग्रेस का कोई सम्मेलन हो, कोई प्रभात फेरी हो अथवा क्रांतिकारियों का कोई आन्दोलन, ऐसे हर अवसर पर यही झंडा गीत बड़े ही जोशीले अंदाज में गाया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के चंद दिनों पहले जब भारत के सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक स्वरूप स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा चली तो 1931 में सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए ध्वज को ही पुनः राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया लेकिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक में पं. नेहरू ने चरखे के स्थान पर इसमें देश की प्रगति, राष्ट्र के कानून और धर्म के पहिये के प्रतीक 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को रखने का सुझाव दिया। संविधान सभा के सभी सदस्य इस सुझाव से सहमत हो गए और उसी दिन से राष्ट्रीय ध्वज को नए रूप में स्वीकार लिया गया। इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए करीब 41 वर्षों का बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा।

पहल

ऋतुपर्ण दत्ते

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।



होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जरूर है, लेकिन बहुत ही तेजी से लोकप्रिय भी हो रही है। यह रोगी के समग्र स्वास्थ्य जिसमें मानसिक और शारीरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करके प्राकृतिक रूप से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत होती है। होमियोपैथी को एक सुरक्षित चिकित्सा पद्धति माना जाता है क्योंकि इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन सोचिए, यही होमियोपैथी यदि कृषि के क्षेत्र में भी उपयोगी साबित हो तो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। इन दिनों दुनिया भार में एग्रो-होमियोपैथी पर लेकर न केवल बड़े-बड़े शोध चल रहे हैं बल्कि तेजी से उपयोग भी बढ़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है।

कृषि क्षेत्र में इसका सफल प्रयोग कई दशकों से हो रहा है। इसकी शुरुआत हालांकि शौकिया तौर पर हुई,

लेकिन जब इसके फायदे नजर आने लगे तो तेजी से शोध और परीक्षण भी होने लगे और लोगों की इसको लेकर उत्सुकता भी बढ़ी। अब नतीजे भी दिखने लगे हैं। होम्योपैथी दवाओं के टिंचर की कुछ बूंदे थोड़े से पानी में मनुष्यों को देकर यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि यह बीमारी की जड़ तक पहुंच उसका समाधान करता है। बस यही फॉर्मूला कृषि क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है।

वास्तव में होम्योपैथिक दवाएं बैक्टीरिया या कीटों को सीधे नहीं मार, पौधों की अपनी जैविक प्रणालियों को प्रभावित करती हैं जिससे वो अपना प्राकृतिक रक्षा तंत्र, जरूरत के हिसाब से विकसित और सक्रिय कर पाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में होम्योपैथी का उपयोग उसी सिध्दांत पर आधारित है जिसमें किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए धीरे-धीरे डायल्यूट दवाओं से किसी बीमारी को काबू किया जाता है जिससे वह जड़ से ही समाप्त हो जाती है। यह पौधों की आनुवंशिक गतिविधियों और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रेरित कर

सकता है, जिससे रक्षा प्रणालियां सक्रिय होती हैं।

देश में एग्रो-होम्योपैथी को लेकर पुडुचेरी प्रयोग खासा सफल और चर्चाओं में है। श्री अरविंदो सोसाइटी (एसएएस) की अगुवाई में एक नई पहचान बन रही है। एग्रो-होम्योपैथी से दोहरा लाभ भी सामने आया। जहां पानी की खपत घटी और इस कारण भूजल स्तर भी बढ़ा। 2018 में शुरू हुई आहार परियोजना में कृषि क्षेत्र में होम्योपैथी के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की सफलता का अंदाज इसी से लगता है कि कुछ ही समय में इसे नाबाढ़ और उसके बाद टाटा ट्रस्ट का समर्थन मिला। वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद जब यह फॉर्मूला खेतों में पहुंचा तो वहां भी बेहद असरकारक रहा। पहले भिंडी उसके बाद धान की उपज में काफी सकारात्मक परिणाम आए। उत्साहित वैज्ञानिकों ने तीनों सीजन रबी, खरीफ और जायद में भी इसकी क्षमता को आजमाया और सकारात्मक नतीजे हासिल किए।इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी जिससे रसायनों पर निर्भरता घटी।

सर्वविदित है कि खेतों में उर्वरकों का छिड़काव करने से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान होता है लेकिन कृषि-होम्योपैथी के मिश्रण ने पत्तियों को नई जान तो दी साथ ही पौधों की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाई। शोधकर्ताओं ने कृषि-होम्योपैथी की लागत को बेहद सस्ती पाया। पहले जहां कृषक 20 से 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर रसायनों पर व्यय करता था, वही होम्योपैथिक दवाओं पर केवल 700 रुपए प्रति हेक्टेयर ही खर्च कर और भी बेहतर परिणाम हासिल करने लगा। यह कमाल ही था जो होम्योपैथिक दवाओं की चंद मिलीमीटर दवाओं ने सैकड़ों लीटर पानी में घुले रसायनों पर भारी पड़ कर असर दिखाया। इससे खेती में हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल रुकने से फसल की चमक और पुष्टता भी बेहतर हुई जिससे किसानों को उपज की अच्छी कीमत मिलने लगी।

होम्योपैथी दवाएं वनस्पतियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को जबरदस्त बढ़ाती हैं। इससे वनस्पतियां, फसल होने वाली बीमारी को अपने आप

ठीक कर लेते हैं। एग्रो-होम्योपैथी में अलग-अलग और बेहद सस्ती चंद मिलीमीटर दवाएं बीजों के अंकुरण से लेकर रोगों से बचाव और फूलने-फलने को बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध हो रही है। ये दवाएं कीट प्रबंधन की दिशा में भी काफी सफल हैं। यहां तक कि फसल में वायरस या बैक्टीरिया के दुष्प्रभावों पर भी असरकारक हैं। वह दिन दूर नहीं जब निरंतर शोध और प्रयोगों के बाद एग्रो-होम्योपैथी की भी ढेरों और अलग-अलग शाखाएं बनना तय है। यह भविष्य का वृहद कृषि पारिस्थितिकी तंत्र होगा। इसमें भी उपचारों की अलग-अलग विधियां होंगी। लेकिन इतना तो तय है कि रसायनों और उर्वरकों के बोझ से आहत मिट्टी को यदि कोई नया जीवन और जहरीले तत्वों से मुक्ति दिलाएगा तो वह होगा भविष्य का एग्रो-होम्योपैथी सेक्टर जहां मिट्टी, पानी अपने मूल स्वरूप में आकर फिर से हमारी प्रकृति में नया जोश भरने का काम करेंगे। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर होम्योपैथी की नई शाखा यानी एग्रो-होम्योपैथी जल्द ही अपनी शानदार धमक दिखाने को तैयार है।

नोटों के संग्रह की अनोखी दीवानगी

बैतूल के रिटायर्ड शिक्षक राजेश के पास हैं, 90 देशों के नोटों का संग्रह

परवेज खान, बैतूल। बैतूल के टिकारी निवासी रिटायर्ड शिक्षक राजेश सूर्यवंशी दुर्लभ नोटों का संग्रह करते हैं। 1970 से जारी नोटों के संग्रह की दीवानगी से उनके पास देशी- विदेशी नोटों का बहुत बड़ा संग्रह है। इस संग्रह में नए-पुराने नोट एवं सिक्के, मिस प्रिंट एवं दुर्लभ नम्बर वाले नोट व सिक्के शामिल है। श्री सूर्यवंशी के इस संग्रह में द्वितीय सेंचुरी के भारतीय सिक्के एवं 1938 के पुराने भारतीय दुर्लभ नोट भी जमा है। इनके संग्रह में लगभग 90 देशों के विदेशी नोट एवं सिक्कों का संग्रह है। इसमें प्रमुख इंडोनेशिया का भगवान श्री गणेशजी का 20000 रुपये का नोट, यूगोस्लाविया का 5 करोड़ का नोट जमा है। जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है।

6 देशों की प्लास्टिक करेंसी उनके पास- श्री सूर्यवंशी के संग्रह में प्लास्टिक करेंसी में मलेशिया, ग्वाटारमाला, हंगकांग, मेक्सिको, नेपाल रोमानिया, ताशकन्द् आदि 6 देशों के नोट है। इन नोटों को आप कभी भी देख सकते है।

अब भारत में प्लास्टिक के नोट निकालने की तैयारी- अब भारत में भी पलास्टिक के नोट चलाए जाने की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक सूत्रों के मुताबिक 10



समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अर्जित ज्ञान का करें उपयोग :कौशलेश तिवारी

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के विद्यार्थियों को दी सम्मानपूर्ण विदाई



बैतूल। आठनेर में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत समाज कार्य के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का सम्मानपूर्वक विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों से अर्जित ज्ञान को समाज सेवा से जोड़ते हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में सभी फायनल ईयर के विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी गईं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड आठनेर की विकासखंड समन्वयक मधु चौहान ने जन अभियान परिषद द्वारा पाठ्यक्रम को चलाने के उद्देश्य एवं पूरे सत्र की गतिविधियों का प्रतिवेदन उपस्थित लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए परिषद के नर्मदापुरम सभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी ने कहा कि सीएमसीएलडीपी पाठ्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा,संवेदना और विकास की रोशनी पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने अध्ययन से अर्जित ज्ञान एवं कौशल का उपयोग समाज के वंचित,जरूरतमंद और कमजोर वर्गों के उत्थान, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक जागरूकता के लिए करें।

जनहित की भावना के साथ कार्य करें: थाना प्रभारी

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आठनेर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि एक सच्चे समाजसेवी की पहचान उसके समर्पण, नैतिकता, जनसेवा और सकारात्मक नेतृत्व से होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नैतिक मूल्यों,सामाजिक उत्तरदायित्वों एवं जनहित की भावना के साथकार्य करें, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।समाज कार्य की यह शिक्षा सभी सार्थक होगी जब उसका प्रत्यक्ष लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचेगा। यही पाठ्यक्रम की मूल भावना भी है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने भी अपने अध्ययनकाल के अनुभव साझा किए तथा संकल्प लिया कि वे समाज के सर्वांगीण विकास, जनजागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में निरंतर सक्रिय रहें। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं को सम्मानपूर्वक विदाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य,सफल जीवन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान की माला कमानाएं व्यक्ति की गईं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आठनेर नगर मंडल अध्यक्ष गोवर्धन राने, जनपद सदस्य राजू सलामें सहित ग्राम विकास प्रस्पुटन समिति के पदाधिकारी एवं मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह का समापन सभी के द्वारा एक साथ समरसता भोज ग्रहण कर किया गया।

डागा-पांसे सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज

कांग्रेस संगठन सृजन प्रशिक्षण में हुआ विवाद पहुंचा थाने

बैतूल। जिले में कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों गुटों में एक दूसरे को कमजोर करने के प्रयास तेज होते जा रहे हैं, जो भविष्य में होने वाले नगरीय निकाय, पंचायत, मंडी एवं सहकारिता सहित अन्य चुनावों के हिसाब से कांग्रेस के लिए हितकर नहीं है। राजनैतिक समीक्षकों का भी यही मानना है कि जिस तरह से कांग्रेस में मतभेद के साथ-साथ मनभेद भी सामने आया है, वह पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे भाजपा अपना राजनैतिक लाभ मिलने की उम्मीद कर रही है।

यह है मामला- लगभग 65 वर्ष पूर्व बैतूल में कांग्रेस को कार्यालय बनाने के लिए भूमि प्राप्त हुई थी। लगभग 40 वर्ष तक कांग्रेस, देश और प्रदेश में सत्ता में रही। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यालय भवन बैतूल में नहीं बना पाई। वहीं 2003 में बैतूल में जमीन मिलते ही पांच वर्षों में भाजपा ने अपना विशाल कार्यालय खड़ा कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस भवन को लेकर जिला कांग्रेस के प्रवक्ता

जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने दिया जा रहा प्रशिक्षण

बैतूल। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निदेशन तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी वंदना जाट के मार्गदर्शन में जनगणना- 2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़ों के संकलन एवं डीसीएचबी पोर्टल के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से जिले में 17 जुलाई से 28 जुलाई तक पीएमश्री शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल में विभिन्न बैचों में प्रशिक्षण संचालित हो रहा है। प्रशिक्षण में जिले के सभी ग्रामीण एवं नगरीय चार्ज अधिकारियों तथा उनके द्वारा नामित क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है।



एवं जिले में निलय डागा के समर्थक माने जाने वाले विजय पारधी ने कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में आल इंडिया कांग्रेस की ओर से आए मध्यप्रदेश प्रभारी हरिश चौधरी को बैतूल में इस बारे में बताया कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस कार्यालय की जमीन पर से अतिक्रमण हटने और भूमिपूजन होने के बाद भी भवन नहीं बना। लेकिन निलय डागा ने अध्यक्ष बनते ही कार्यालय का काम चालू कर दिया। इसी बात को लेकर कांग्रेस का दूसरा गुट विजय

पारधी से नाराज हो गया और जैसे ही हरिश चौधरी खाना हुए, तो विजय पारधी के साथ धक्का-मुक्का का वीडियो भी वायरल हो गया। जिसको लेकर विजय पारधी ने देर शाम थाने में शिकायत दर्ज की। मिली जानकारी के अनुसार विजय पारधी की शिकायत की जानकारी मिलते ही आमला से दो बार कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर हारने वाले मनोज मालवे ने भी एक शिकायत कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज कर लिया है।

हरियाली बढ़ाने को लेकर नगर पंचायत परिषद के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों ने किया सीड बॉल वृक्षारोपण

सोहागपुर। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निदेशन के अनुसार नर्मदापुरम जिले में हरियाली बढ़ाने को लेकर नवांकुर अभियान के अंतर्गत नगर पंचायत परिषद ने सीड बॉल वृक्षारोपण महाअभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत परिषद के तत्वावधान में बीज बैंक के माध्यम से तैयार लगभग 4000 सीड बॉल को नगर के शोभापुर रोड स्थित अटल अमृत उद्यान से लेकर नहर के पास, विभिन्न खाली एवं उपयुक्त स्थानों पर डाला गया। वर्तमान में वर्षा ऋतु के दौरान सीड बॉल में मौजूद बीजों के अंकुरित होने से विभिन्न स्थानों पर नए पौधों के विकसित होने की संभावना है। इस हरियाली बढ़ाने के उल्कृष्ट आयोजन नगर पंचायत परिषद ने नागरिकों की सहभागिता के लिए गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया था।इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष लता यशवंत पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, उपाध्यक्ष आकाश खुबंशी, पार्षद रविशंकर उड्डेक, पार्षद आशीष



विश्वकर्मा, संघा नागवंशी,नौरज मलैया, नगर पंचायत परिषद के समस्त कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक एवं मातृशक्ति उपस्थित थीं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार विगत 02 माह से सीड बाल का निर्माण किया जा रहा था। जिसमें अनेकों प्रकार के बीज को

इनके खिलाफ हुआ है मामला दर्ज

कोतवाली टीआई देवकरण डेहरिया ने बताया कि विजय पारधी की शिकायत पर अपराध क्रमांक 602/ 26 के तहत पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, सलमान खान, मनोज मालवे और नवनीत मालवीय के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। वंही मनोज मालवे की शिकायत पर अपराध क्रमांक 605/ 26 के तहत जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक निलय डागा, विजय पारधी, मोनू बडोनिया और हर्षवर्धन धोंटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मारपीट, गाली-गलौज की धाराओं के अलावा एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रेत और मुरुम के अवैध परिवहन में सलिप्त 2 वाहनों को किया जप्त

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निदेशानुसार जिले में अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 18 और 19 जुलाई को खनिज विभाग द्वारा खनिज अमले के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। खनिज अमले द्वारा गौण खनिजों के अवैध परिवहन में सलिप्त वाहनों पर कार्यवाही करते हुए उन वाहनों को जप्त कर समीपस्थ पुलिस थानों की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ घोड़ाडोंगरी क्षेत्रांतर्गत खनिज मुरुम के अवैध परिवहन में सलिप्त 01 वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 0735 को जप्त कर पुलिस चौकी घोड़ाडोंगरी की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है एवं बैतूल क्षेत्रांतर्गत ग्राम खेड़ीसांवलीगढ़ के पास से खनिज रेत के अवैध परिवहन में सलिप्त 01 वाहन जॉन डियर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 48 एच 1136 को जप्त कर पुलिस चौकी खेड़ीसांवलीगढ़ की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। उपरोक्त अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर प्रकरणों को न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पहुंचाकर प्राकृतिक रूप से पौधों के अंकुरण को बढ़ावा देकर नगर में हरित क्षेत्र को विस्तार करना है। सीड बॉल वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने एक अभिनव एवं प्रभावी पहल है, जिसमें कम संसाधनों के माध्यम से अधिक से अधिक स्थानों पर हरियाली विकसित की जा रही है। इस अवसर पर संजय परसाई, दयाशंकर कुडूमो, हनुमन्त पारते, भूपेंद्र केवट, हरगोविंद व्यास, प्रबुद्ध दुबे, अनिल खुबंशी, नरेंद्र धुर्वे,लक्ष्मीनारायण मालवीय, कपिल सोनी, राधेश्याम खुबंशी, रणधीर खुबंशी, राजेश खुबंशी, लाल बहादुर आनवंशी,नौरज मलैया, पवन कुमार, घनश्याम पठरिया, प्रवेश ठाकुर, प्रह्लाद किार आदि उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

दो प्रकरण में नगद इनाम की घोषणा

विदिशा (निप्र)। पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के द्वारा थाना नटेरन जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 172/2026 के फरार आरोपी जितू उर्फ जितेन्द्र कुशवाह निवासी गंजबासौदा तथा देहात गंजबासौदा जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 209/2026 के फरार अज्ञात आरोपी की सूचना देने वालो को क्रमशः तीन-तीन हजार रूपए नगद राशि देने की उद्घोषणा की है। सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

वॉटरफॉल एवं जोखिमपूर्ण स्थानों पर जा रहे लोगों को लौटाया जा रहा वापस

कलेक्टर ने वर्षाकाल में जोखिमपूर्ण स्थलों पर न जाने की नागरिकों से की अपील



सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के. के निर्देशानुसार वर्षाकाल में नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी वॉटरफॉल, डैम, जल पर्यटन स्थलों एवं अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावों हैं। इन स्थानों पर वर्षा के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए राजस्व, वन, पुलिस तथा अन्य विभागों के मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि पर्यटकों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से रोका जा सके तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। कलेक्टर के निर्देशानुसार अमरगढ़, दिगंबर और कालियादेव वॉटरफॉल सहित इन सभी दुर्घटना संभावित स्थलों पर नागरिकों को जाने से रोकने के लिए इनके पहुंच मागों पर टीमें तैनात की गई हैं। टीम द्वारा इन स्थानों पर जा रहे लोगों को प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी देकर वापस लौटाया जा रहा है। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करें। नागरिकों का जीवन एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्षाकाल में जिले के इन पर्यटन स्थलों पर सीहोर के साथ-साथ भोपाल से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने तथा सुरक्षित व्यवहार अपनाने की अपील की है।

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना से 49 जस्टरतमंद मरीजों को मिली राहत

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 49 मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न अस्पतालों को ई-पेमेंट के माध्यम से सहायता राशि जारी की है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह राशि सीधे संबंधित अस्पतालों के बैंक खातों में भेजी गई है, जिससे मरीजों का उपचार बिना किसी आर्थिक बाधा के जारी रह सके। जारी सूची के अनुसार जिले की तहसील क्रमशः नटेरन, लटेरी, कुरवाई, गंजबासौदा, सिरोंज, विदिशा, शमशाबाद, ग्यारसपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के मरीजों को योजना का लाभ मिला है। सहायता राशि 15 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक स्वीकृत की गई है। योजना के तहत जिन प्रमुख अस्पतालों को उपचार राशि जारी की गई उनमें जीवानंद मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, राजधानी हॉस्पिटल, जिल्दल हॉस्पिटल, केयरवेल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, विधाता मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अरेरा हॉस्पिटल एंड कैथ लैब, एम्स भोपाल, जीवन ज्योति मल्टीकेयर ट्रॉमा सेंटर, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, गट-जी एंड लीवर हॉस्पिटल, सर्वोत्तम हॉस्पिटल, भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल, सागर मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मैक्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लीलावती मेमोरियल हॉस्पिटल, सुश्रुत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अक्व मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, न्यू एरा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, हर हेल्थ हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, डॉ. जी.एम. ताओरी सोआईएमएस हॉस्पिटल नागपुर, लक्ष्मी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, काउटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एबीएम हॉस्पिटल, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, बेरसिया जनरल हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल, लेकसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल साइंस तथा बंसल हॉस्पिटल भोपाल शामिल हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर 99 हजार की साइबर ठगी

केरल और मुंबई से दो आरोपी गिरफ्तार, कस्टमर केयर पर किया था कॉल



नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में ऑनलाइन शॉपिंग और फर्जी कस्टमर केयर के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के दो आरोपियों को नर्मदापुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देहात थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर केरल और महाराष्ट्र (मुंबई) में दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ा। दोनों आरोपी ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। इनमें से एक मुंबई के विजय नगर औद्योगिक क्षेत्र में चौकीदारी कर रहा था। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर नर्मदापुरम ले आई है।

कस्टमर केयर नंबर खोजते ही ठगी का शिकार हुई महिला

मामला 18 मार्च 2026 का है। रसूलिया निवासी रूबी फौजदार ने ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किए थे और फोनपे के जरिए 9 हजार रुपए का भुगतान किया था। भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि नहीं हुई। जानकारी लेने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर खोजकर कॉल किया। फोन उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया। उसने पैसे वापस करने का झांसा देकर महिला के बैंक खाते से 99 हजार रुपए निकाल लिए। इसके बाद महिला ने देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई।

तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

मामले की जांच के दौरान पुलिस और साइबर सेल ने बैंक खातों के लेनदेन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। जांच में आरोपियों की लोकेशन केरल और महाराष्ट्र में मिली। पुलिस की टीम सबसे पहले केरल के बटकारा पहुंची। वहां से विकास बाथम निवासी ग्राम देवरीकला, थाना बेलगढ़, जिला ग्वालियर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपने साथी दीपक रावत निवासी देवरीकला, जिला ग्वालियर का नाम बताया। दीपक रावत उस समय मुंबई के विजय नगर औद्योगिक क्षेत्र में चौकीदारी कर रहा था। पुलिस से मुंबई पहुंचकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को नर्मदापुरम लाया गया है। उन्हें रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बालिका गृह से लापता 5 नाबालिग केस में एसआईटी गठित

बीजेपी नेता की है संस्था, जांच करने पहुंचे पुलिस अफसर, बच्चियों से भी की बात

नर्मदापुरम(निप्र)। नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित मुस्कान बालिका गृह से 5 नाबालिग लड़कियों के लापता होने के मामले में नर्मदापुरम एसपी साई कृष्णा एस. थोटा ने एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) गठित की है। टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। शनिवार शाम एसपी अभिषेक राजन के नेतृत्व में इटारसी एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा, इटारसी थाना प्रभारी सौरभ पांडे, महिला थाना प्रभारी राखी मौरी, पथरौटा थाना प्रभारी मोनिका गौर, महिला एसआई श्रद्धा राजपूत और अन्य अधिकारी मुस्कान बालिका गृह पहुंचे। अधिकारियों ने संस्था की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और वहां रह रही बच्चियों से अलग-अलग बातचीत कर जानकारी जुटाई।

दो साल में 5 लड़कियां लापता

पुलिस के अनुसार जुलाई 2024 में एक, दिसंबर 2025 में तीन और 14 जून 2026 को एक नाबालिग लड़की लापता हुई थी। इस तरह



कुल पांच लड़कियां लापता हैं। फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वे कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं। इस जांच में साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। पुलिस लड़कियों के परिजनों के भी बयान दर्ज करेगी। 17 जुलाई की रात इटारसी थाने में पांचों नाबालिगों की गुमशुदगी दर्ज कर मामले की

जांच शुरू की गई है।

कलेक्टर को भी लिखा गया पत्र

एसपी नर्मदापुरम ने मामले को लेकर कलेक्टर को भी पत्र लिखा है। इसमें लड़कियों की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी का उल्लेख किया गया है। साथ ही संस्था में

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

बैतूल, (निप्र)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 18 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप संचालक कृषि श्री राम गोपाल रजक ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषकों को जागरूक करना एवं कृषकों को प्राकृतिक कारणों से होने वाले जोखिमों की जानकारी के बारे में बताया एवं व्यक्तिगत क्षति की भरपाई के लिए किस-किस तरीके से सूचनाओं को कैसे दर्ज करते हैं एवं सर्वे कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि बैतूल जिले में खरीफ मौसम 2026 कृषकों के फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवा कर जोखिमों एवं फसल बीमा के हित लाभ के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वर्तमान खरीफ मौसम 2026 में अधिसूचित फसलों के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि सोयाबीन के लिए 850 रुपए , मक्का 722 रुपए, धान सिंचित के लिए 838 रुपए, धान असिंचित 660 रुपए तथा अरहर के लिए 740 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई हैं। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31

जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने के इच्छुक किसान अपनी निकटतम बैंक शाखा सहकारी समिति अधिकृत चैनल एवं जन सेवा केंद्र सीएससी एवं कृषकों को प्राकृतिक कारणों से होने वाले जोखिमों की जानकारी के बारे में बताया एवं व्यक्तिगत क्षति की भरपाई के लिए किस-किस तरीके से सूचनाओं को कैसे दर्ज करते हैं एवं सर्वे कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि बैतूल जिले में खरीफ मौसम 2026 कृषकों के फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवा कर जोखिमों एवं फसल बीमा के हित लाभ के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वर्तमान खरीफ मौसम 2026 में अधिसूचित फसलों के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि सोयाबीन के लिए 850 रुपए , मक्का 722 रुपए, धान सिंचित के लिए 838 रुपए, धान असिंचित 660 रुपए तथा अरहर के लिए 740 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई हैं। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31

दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत जिले में पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन के लिए किया जागरूक



बैतूल (निप्र)। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तृतीय चरण के अंतर्गत जिले के विभिन्न विकासखंडों में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पशुपालकों से संवाद कर उन्हें वैज्ञानिक पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान शासन की विभिन्न पशुपालन एवं दुग्ध विकास योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाकर आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के तहत विकासखंड शाहपुर के ग्राम भौरा में घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगा सजजन सिंह उईके एवं भूतपूर्व जनपद सदस्य श्री अशोक सिरोटिया ने पशुपालकों को नस्ल सुधार, पशु पोषण एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान पशुपालकों को गौस ऐप की जानकारी दी गई तथा अभियान से संबंधित रील भी साझा की गई।

क्षीरधारा ग्राम के संबंधित पशुपालक को माननीय विधायक द्वारा चरी-चारा बीज का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में विकासखंड पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. राहुल सिंह एवं सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी श्री मुकुल चौधरी उपस्थित रहे। विकासखंड मुलताई के ग्राम मुलताई में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जिला पंचायत बैतूल अध्यक्ष श्री राजा पवार ने पशुपालक श्री प्रदीप पवार के यहां निरीक्षण एवं संवाद किया। इस अवसर पर उन्नत नस्ल के लिए कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स-सॉर्टेड सीमेन के उपयोग, संतुलित आहार, सायलेज, मिनरल मिक्सचर, कृमिनाशक दवाओं के नियमित उपयोग तथा समय-समय पर टीकाकरण सहित आधुनिक वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों की जानकारी दी गई। साथ ही वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक पशुपालन अपनाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने तथा

अधिकतम आर्थिक लाभ अर्जित करने के उपायों से अवगत कराया गया। पशुपालक द्वारा बताई गई आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। इस अवसर पर संयुक्त संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग भोपाल डॉ. सुनील परनाम तथा उप संचालक बैतूल डॉ. सुरजीत सिंह उपस्थित रहे।

इसी क्रम में पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक , विधानसभा घोड़ाडोंगरी श्री रामजीलाल उईके ने दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तृतीय चरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. कीर्ति ठाकरे एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी श्री मनीराम अहाके उपस्थित रहे। श्री उईके ने पशुपालकों से विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें गौस ऐप का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। विकासखंड के ग्राम बोरदेही में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने पशुपालक श्री अरविंद से संवाद किया। इस दौरान दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं के संतुलित पोषण तथा वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर डॉ.सोनवणे ने विशेष रूप से पशुओं को नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर खिलाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके नियमित उपयोग से पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, दुग्ध उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार होता है तथा खनिज तत्वों की कमी से होने वाली समस्याओं की रोकथाम होती है।



शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी कर रहे पानी के प्लांटों का निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा पानी के प्लांटों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका के कार्यपालन यंत्री श्री विजय कोली एवं उपयंत्री श्री वैभव लोवानिया द्वारा काहरी प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल की गुणवत्ता जांचने के लिए आवश्यक ऑनलाइट टेस्ट किए गए और नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

तीर्थ दर्शन योजना: 260 श्रद्धालु हरिद्वार-ऋषिकेश रवाना



केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उईके ने दिखाई हरी झंडी

बैतूल (निप्र)। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बैतूल जिले के लगभग 260 श्रद्धालुओं को रविवार को हरिद्वार-ऋषिकेश की चार दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उईके ने बुजुर्ग यात्रियों का पुष्पहार पहनाकर आत्मीय स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया तथा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती इंदिरा महतो सहित अन्य

अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री श्री उईके ने कहा

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री उईके ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों के सम्मान और उनकी आस्था को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जीवनभर परिवार और समाज की सेवा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का अवसर देना सरकार की संवेदनशील सोच का परिचायक है। उन्होंने यात्रियों से यात्रा के दौरान

आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने, देश की सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने तथा प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी यात्रियों के सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यह हरिद्वार-ऋषिकेश यात्रा 19 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित की जा रही है। यात्रा के लिए बैतूल जिले से कुल 260 यात्रियों का चयन किया गया है। यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक चिकित्सक, पांच आरक्षक तथा पांच अनुरक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस विशेष तीर्थ यात्रा में बैतूल के साथ नर्मदापुरम एवं सागर जिले के श्रद्धालु भी सहभागी हैं।

